● वर्ष-4
● अंक-120
रायपुर, रविवार
29 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन

राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाने की घोषणा

नई दिल्ली। शनिवार को निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। केंद्रीय सरकार ने मनमोहन सिंह के सम्मान में एक जनवरी 2025 तक सात दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व पीएम का स्मारक बनाने की घोषणा की।

इससे पहले सुबह 8:30 बजे से उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया, जहां पार्टी कार्यकर्ता व आम जनता ने उनके दर्शन किए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी कार्यालय में उपस्थित थीं। यहां पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अंतिम बार पूर्व पीएम को नमन किया। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को अंतिम सलामी दी गई। तीनों सेनाओं ने मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निगमबोध पहुंचे।

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरीशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिन भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निगम बोध घाट पहुंचें। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को अंतिम बार निगम बोध घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी के अलावा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह आदि ने निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को दी अंतिम श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निगम बोध घाट पर देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी।

छत्तीसगढ़ के पहले पार्क के लिए एनआरडीए ने दी 142 एकड़ जमीन

नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क

रायपुर। एनआरडीए ने दी 142 एकड़ जमीनछत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्युटिकल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फार्मास्युटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि हेतु नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना के लिए 141.84 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ ही फार्मास्युटिकल क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं आम लोगों को सहजता से सुलभ हो, इस सोच के साथ राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में प्रभावी इको सिस्टम तैयार करने की लगातार पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाना है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और जनोन्मुख बनाना जरूरी है। फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना इसी की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में भी फार्मास्युटिकल क्षेत्र के उद्योगों

को कई अनेक सुविधाएं और रियायतें दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि होने के साथ ही फार्मास्युटिकल क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावाएनआरडीए ने दी 142 एकड़ जमीन मिलेगा एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होने के साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना से घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की बढ़ती मांग को हम आसानी से पूराकर पाएँगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है जिसे आने वाले समय में 10 लाख रूपए तक किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत विशेष स्थितियों में इलाज के लिए 25 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि फार्मास्युटिकल पार्क में आयुष उत्पादों में विशेषज्ञता वाली फार्मास्युटिकल इकाइयों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पार्क फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होगा। अनुसंधान और विकास केंद्र और परीक्षण प्रयोगशाला जैसी आवश्यक सेवाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फार्मास्युटिकल सेक्टर में वृहद उद्यम हेतु परियोजना में स्थायी पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 100 प्रतिशत तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रावधान है। फार्मास्युटिकल इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से लेकर 12 वर्ष तक भुगतान किये गए नेट एसजीएसटी अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति किए जाने अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस को अपना इतिहास याद रखना जरूरीः नड्डा

नईदिल्ली। राहुल गांधी ने निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि पूर्व वित्त मंत्री सर्वोच्च सम्मान और स्मारक के पात्र हैं। वहीं, भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह को जीते जी कभी सम्मान न देने वाली कांग्रेस अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने सोनिया गांधी को पीएम मनमोहन सिंह से ऊपर सुपर पीएम बनाकर पीएम पद की गरिमा को तार-तार कर दिया था। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़कर पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया। और आज वही राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के किसी भी बड़े नेता को न तो सम्मान दिया और न ही उनके साथ न्याय किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या विपक्ष के, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, पीवी नरसिम्हा राव हों, प्रणब दा हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीएम मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दे दी है और परिवार को भी सूचित कर दिया है। फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। कांग्रेस का इतिहास याद रखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की मांग उठी थी। लेकिन उस समय सोनिया गांधी ने इसे खारिज कर दिया था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने 2015 में उनके लिए एक स्मारक की स्थापना की थी। जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, तो कांग्रेस कार्य समिति को इसकी परवाह तक नहीं हुई शोक सभा बुलाने के लिए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बचना चाहिए।

पीएम मोदी ने की भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश से मुलाकात, विश्व शतरंज विजेता बनने पर बधाई दी

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश से मुलाकात की और उन्हें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए बधाई दी। इस दौरान गुकेश के माता-पिता भी मौजूद रहे। बता दें कि, इसी महीने गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया था। लिरेन को हराकर वह सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतिहास रच दिया। पीएम आवास में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा – शतरंज चैंपियन और भारत के गौरव डी गुकेश के साथ शानदार बातचीत हुई।

प्रमुख समाचार

राजकीय शोक में कार्यक्रम में शामिल हुए केरल के सीएम

नईदिल्ली। केरल में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर के बीच राय में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधिकारिक उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। कोचि में पत्रकारों से बात करते हुए राय विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री के इस कदम को अपमानजनक और अनुचित बताया। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि दस साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार नई दिल्ली में हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जैसे किसी व्यक्ति का कोचि हवाई अड्डे पर आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होना और उसका उद्घाटन करना अपमानजनक और अनुचित है। उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था और हवाई अड्डे के प्रबंधन से अनुरोध किया गया था कि वह समारोह को स्थगित कर दें और एक दिन पहले मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचित करें। वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री के इस व्यवहार पर अपना दुख और विरोध व्यक्त किया है।

बाहर भंडारा लगा दो, भिड़ लग जाएगी: संदीप दीक्षित

नईदिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर महिलाओं को 2,100 रुपये देने के आप के चुनावी वादे, कांग्रेस उम्मीदवारों के आवासों के पास पंजाब खुफिया अधिकारियों की मौजूदगी के आरोपों और कथित आवाजाही की जांच करने को कहा है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित की शिकायतों के बाद ये निर्देश जारी किए गए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। हालांकि, संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि जिस भी योजना में आप पैसा बांटेंगे वह मशहूर हो जाएगी, बाहर भंडारा लगा दो, भिड़ लग जाएगी। उन्होंने महिलाओं को दोबारा निर्वाचित होने पर 2100 रुपये देने की योजना की घोषणा की, एक पार्टी होने के नाते वे ऐसा कर सकती हैं। हमारा सवाल यह था कि उन्होंने पंजाब में 1500 रुपये देने की ऐसी ही योजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यह मुहैया नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी ने कहा कि हम महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं।

वक्फ बोर्ड पर हिंदू-मुस्लिम न करें साधु-संत-मौलाना बरेलवी

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ के मेले की शुरुआत होने जा रही है। उसमें साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने से संबंधित बोर्ड व बैनर लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ में तमाम धार्मिक व्यक्तियों, साधु-संतों, अखाड़ा परिषद वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न करें। वक्फ बोर्ड का मामला सरकार और मुसलमानों के दरम्यान है। उसको इसी तरीके से हल करेंगे। हम सरकार के सामने अपनी बात प्रमुखता से रख रहे हैं और रखते रहेंगे, इसमें साधु-संतों की जरूरत नहीं है। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ मेले में सनातन बोर्ड के संबंध में भी बोर्ड लगाए गए हैं। हम साधु-संतों की इस मांग का समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड के गठन में आने वाली अड़चनों के हल के लिए और केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से रखने के लिए मुसलमान साधु-संतों के साथ खड़ा हो सकता है। रजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर साधु-संत देश में हिंदू मुस्लिम न करें, बल्कि उनका काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है वही करें तो बेहतर होगा।

प्रदर्शन में शामिल हुए प्रशांत किशोर, बुलाई छात्र संसद

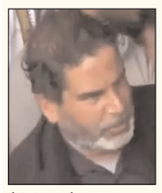

नईदिल्ली. जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग के उन अभ्यर्थियों के साथ शामिल हो गए हैं जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा की दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि सबने मिलकर तय किया है कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए... कल सभी छात्र, सभी युवा, अपने भविष्य को लेकर चिंतित लोग एक साथ गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठेंगे और मिलकर योजना तय की जायेगी कि कैसे बिहार के छात्रों का भविष्य बचाया जा सकता है। किशोर ने आगे कहा कि ये पूरा आंदोलन छात्रों का है, इसका नेतृत्व छात्र ही करेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसे कोई नीतीश कुमार, कोई नेता लाठीतंत्र नहीं बना सकता। इससे पहले शुक्रवार को पटना के गर्दनीबाग में छात्रों से बात करते हुए, किशोर ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की और एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार से दो बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 1-2 साल से लोकतंत्र को लाठीतंत्र में बदल दिया गया है।

अजरबैजान विमान मामला- राष्ट्रपति पुतिन ने माफी मांगी

मॉस्को। रूस ने शनिवार को माना कि उसके वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को विफल करने के प्रयास में अजरबैजान एयरलाइंस के विमान को मार गिराया। क्रेमलिन ने कहा कि विमान रूस के ग्रोज्नी हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी रूस के कई क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हादसे को लेकर माफी मांगी है। कजाखस्तान के अक्तौ में बुधवार की दोपहर करीब 12.30 बजे अजरबैजान एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें 38 लोगों की जान चली गई थी। विमान में चालक दल के पांच सदस्यों सहित 62 लोग सवार थे। यात्री अजरबैजान, रूस, कजाखस्तान और किरगिस्तान के नागरिक थे। विमान अजरबैजान की राजधानी बाकू से उड़ान भरने के बाद रूस के दक्षिणी क्षेत्र ग्रोज्नी की ओर जा रहा था। लेकिन विमान एक धमाके के साथ कजाखस्तान के अक्तौ शहर के पास गिर गया था। क्रेमलिन ने इस बात को कबूल किया है कि रूसी वायु रक्षा बल यूक्रेन के सिलसिलेवार ड्रोन हमलों को विफल करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय विमान रूस के ग्रोज्नी में उतरने का प्रयास कर रहा था।

मनमोहन सिंह स्मारक विवाद:

कांग्रेस की सरकार होती तो मनमोहन सिंह को दिल्ली में जमीन नसीब न होती

पंकज झा

प्रणव दा कोई अकेले नहीं थे। ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता जिनका कद बड़ा हो गया, वे नेहरू-फिरोज परिवार के निशाने पर रहे। कांग्रेस के हर बड़े नेता से नफरत सा रहा सोनिया परिवार को। प्रणव मुखर्जी जी को भारत रत्न भी श्चठ्ठह्लद्गठ-स्त्रह्लड्डद्बश्स्त्रद्ब जी ने दिया।

आदरणीय मनमोहन सिंह जी के अध्यादेश को उसी हिकारत के साथ फाड़ कर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था श्चऋड्डद्धह्वद्यत्नड्डठ्ठस्त्रद्धद्ब ने जिस हिकारत के साथ आज धर्मग्रंथ जलाये जा रहे हैं।

तय मानिए, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती न तो दिल्ली में दो गज जमीन तो नसीब होना छोड़िए, दिल्ली के किसी सार्वजनिक शवदाह गृह तक में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने देती सोनियाजी।

ऐसा यूं ही नहीं कह रहा। याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा रावजी, जिनकी सरकार में वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंहजी ने वैश्विक यश प्राप्त किया था, उनके साथ क्या किया था सोनियाजी ने? वे कांग्रेस मुख्यालय में भी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन हेतु रखने को तैयार नहीं थी। जब अत्यधिक दबाव के कारण नरसिम्हा राव जी को लाना पड़ा, तब मात्र 11 लोग उपस्थित थे, उनके दर्शन के लिए। कोई पूछेगा आज कांग्रेस से कि उतने बड़े व्यक्तित्व और विद्वान पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि कहां है? हैदराबाद में उनके अंतिम संस्कार करने पर क्यों विवश किया गया। केवल इसलिए, क्योंकि सोनिया परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और बड़ा कद दिल्ली में दिखे जो राजीव खानदान का न हो। नरसिम्हा राव जी से सोनिया गांधीजी के घृणा का एक कारण यह भी था कि उन्होंने श्रीअयोध्या में लाशें नहीं बिछने दी।

केवल प्रणव दा, नरसिम्हा रावजी, मनमोहन सिंह जी का भी प्रश्न नहीं है। याद कीजिए, प्रातः स्मरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या किया गया?

भारत रत्न प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जैसा

व्यवहार किया नेहरूजी ने उसे जान कर तो आप रो पड़ेंगे। सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें दिल्ली में रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मिला। भारत का पहला राष्ट्रपति, जो अस्थमा के गंभीर मरीज थे, उन्हें अपना शेष जीवन पटना के सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में गुजारना पड़ा। मृत्यु भी उनकी पटना में हुई और दिल्ली में कोई समाधि या संस्कार की व्यवस्था तक नहीं की गयी। नेहरुजी शामिल भी नहीं हुए। तब के राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को भी उन्होंने मना किया था, पर वे नहीं माने थे। क्योंकि सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार में नेहरुजी के मना करने के बावजूद शामिल हुए थे प्रथम राष्ट्रपति, इसलिए नेहरू की घृणा इस रूप में निकली थी। पोस्ट में वर्णित हर तथ्य के दस्तावेजी प्रमाण हैं।

सरदार पटेल से लेकर नेहरूजी के परिवार से पीड़ित कांग्रेस नेताओं की, कांग्रेस (इंदिरा) के ऐसे दुष्कृत्यों की लंबी सूची है। अगर इनकी सरकार रहते अटलजी का निधन हुआ होता, तो जैसा इनका इतिहास है, उसके अनुसार तो अटलजी को भी दिल्ली में स्थान नहीं मिलता। मनमोहन सिंहजी का महाप्रयाण आज इस तरह समादृत हो रहा है, उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र इस संपूर्ण गरिमा, आदर के संग याद कर रहा है, उन्हें अश्रुमिश्रित श्रद्धांजलि मिल रहा है, तो केवल इसलिए क्योंकि आज कथित गांधी परिवार कुछ भी खराब करने की स्थिति में नहीं है।

मनमोहन सिंहजी को रिमोट की तरह ही सही, पीएम उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि सिख नरसंहार का कलंक थोड़ा धो कर वह वोट बटोरना चाह रही थी। कांग्रेस और उसके पेड ईको सिस्टम के गाल बजाने, उस थोथे चना के घना बजाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। रक्तरंजित ही नहीं, कलंक रंजित भी रहा है नकली गांधियों वाले कांग्रेस का इतिहास!

कांग्रेस ने पूर्व पीएम की गरिमा को ठेस पहुंचाई-भाजपा

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक बनाने को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई थी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कद के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए, जहां उनका स्मारक भी बनाया जा सके। इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि, पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए स्थान न ढूंढ़ना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया गया है, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, यह भारत की राजनीति में एक नया निम्न स्तर है, जिसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी के कारण – हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया गया था... भाजपा का मानना है कि मृत्यु में गरिमा होनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, खासकर राहुल गांधी – जिन्होंने दाह संस्कार के बारे में ट्वीट किया है, वह शर्मनाक है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद हमने कैबिनेट की बैठक में फैसला किया कि चूंकि वह प्रधानमंत्री थे और उनका कद बड़ा था – कैबिनेट ने कांग्रेस और डॉ. मनमोहन सिंह के परिवार को एक पत्र लिखा – जिसमें कैबिनेट ने कहा कि हमें उनके नाम पर एक स्मारक बनाना चाहिए ताकि देश और दुनिया उन्हें उनके सकारात्मक कार्यों के लिए याद रखे।

अंडरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

कोरबा। कोरबा चांपा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 149 में बरपाली चौक पर ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है। बरपाली गांव के महिलाओं ने हाथ में रस्सी लेकर सड़क पर खड़ी हो गई है। नेशनल हाइव के नीचे से अंडर ब्रिज मार्ग की मांग कर रहे है। सैकड़ों महिलाओं ने चक्काजाम किया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई है इस जाम में यात्री गाड़ी भारी वाहनों के अलावा चारपहिया और बाइक सवार फंसे हुए है। सड़क के दोनों तरफ भारी वाहनों की लंबी कथा लगने की वजह से लोग काफी परेशान है सुबह से ही महिलाएं आंदोलन पर है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें सड़क पार करने काफी दूरी तय करना पड़ेगा वहीं अंडर ब्रिज मार्ग नहीं होने से हादसे भी हो सकते हैं।

पुष्पा बाई ने बताया कि बरपाली की निवासी है और इस नेशनल हाईवे के बनने के बाद से उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सड़क के उसे तरफ उसका घर है और नेशनल हाईवे बनने के बाद उसे स्टेशन बाजार और उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा निस्तार के लिए तालाब भी जाना होता है और अंडर ब्रिज का निर्माण नहीं होने के कारण उन्हें काफी लंबी दूरी तय कर जाना पड़ेगा जिससे भविष्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इन बातों को लेकर आज वह सड़क पर उतरी हुई है।

वहीं ग्रामीण भगवती यादव ने बताया कि नेशनल हाईवे बनते समय उन्हें लगा कि एक नीचे से रास्ता होगा लेकिन नहीं होने के कारण उन्हें भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इन सब बातों को लेकर गांव के सभी महिलाएं आज चक्का जाम कर अपनी मांग शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं। वहीं इसकी सूचना उरगा थाना पुलिस को दी गई जहां मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी यहां नहीं पहुंचेंगे और उनकी बातें अगर नहीं मानी गई तब तक वह चक्काजाम पर बैठे रहेंगे।

ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्राधिकारी का किया घेराव

कोरबा कोलगा के कैलाश गुफा मार्ग स्थित जंगल में किए जा रहे कूप कटिंग काम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काम बंद कराने के बाद ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्राधिकारी घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीण अधिकारियों को हटाने की मांग पर अड़े रहे।

कोरबा वनमंडल के वन परिक्षेत्र पसरखेत में 21 नवंबर को सलेक्शन कम इम्प्रुवमेंट (एसीआई) के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। यह कार्यक्रम कक्ष क्रमांक 1128 में चल रहा था। कार्यक्रम में सीसीएफ प्रभात मिश्रा व डीएफओ अरविंद पीएम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मौके पर पहुंचे कोलगा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जता दिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने जंगल को कोलगा समिति का बताते हुए कूप कटिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। ग्रामीणों के विरोध के बाद वार्ता का दौर चलता रहा। इसके बाद भी बात नही बनी। वन विभाग ने सप्ताह भर पहले कैलाश गुफा मार्ग स्थित जंगल में कूप कटिंग का काम शुरू करा दिया था। इसके लिए पसरखेत के मजदूर लगाए गए थे, जो कुल्हाड़ी सहित अन्य औजार की मदद से पेड़ की कटाई कर रहे थे। जिसकी भनक कोलगा के ग्रामीणों को लग गई। ग्रामीण पेड़ कटाई के विरोध में लामबंद हो गए। महिला समिति के सदस्य भारी संख्या में एकत्रित हुई। वे लाठी डंडे से लैस होकर मौके पर जा पहुंचे। महिलाओं ने पेड़ कटाई का विरोध शुरू कर काम बंद करा दिया था। शुक्रवार को पुन: ग्रामीणों ने पसरखेत रेंज आफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। कूप कटिंग का विरोध करते हुए वे अधिकारियों को अन्यत्र हटाने की मांग करते रहे।

कूप कटिंग को लेकर एक तरफ जहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं अधिकारियों को हटाने की मांग भी हो रही है, लेकिन इस मामले में अधिकारियों को हटाना हल नहीं हो सकता। नए अधिकारी भी विभागीय आदेश के तहत कार्य को आगे बढ़ाएंगे ही। बताया जा रहा है कि वर्षों पहले कोलगा समिति में करीब दो दर्जन कक्ष समाहित थे। विभाग द्वारा तराईमार को कोलगा से पृथक कर नए समिति का गठन किया गया। जिससे करीब डेढ़ दर्जन कंपार्टमेंट तराईमार समिति में चला गया। तत्कालिन अधिकारियों द्वारा समिति विभाजन को लेकर ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया गया था। जिसके चलते विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है।

एमसीबी में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, हड़कंप

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एमसीबी में खनिज विभाग ने प्यारे ग्रुप पर दबिश देकर मोबाइल क्रशर सीज किया है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने उन्हें नोटिस भी थमाया है। महराजपुर के आश्रित ग्राम दर्री टोला में खनिज विभाग ने शुक्रवार को दबिश दी।

एमसीबी खनिज निरीक्षक आदित्य मानकर ने बताया कि दर्री टोला में प्यारे लाल साहू के खदान की जांच की गई। इस मौके पर काफी अनियमितता पाई गई। जिसके बाद प्यारे लाल साहू को नोटिस दिया गया। साथ ही पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। खनिज निरीक्षक ने बताया कि बरबसपुर स्थित लक्ष्मण मिश्रा के क्रेशर के पास मोबाइल क्रेशर स्थापित किया गया। जिसके बारे में पूछताछ करने पर भूमि स्वामी लक्ष्मण मिश्रा ने पीआर कंपनी का क्रेशर होना बताया। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी कि विधिवत सहमति देकर क्रेशर लगाया गया।

आदित्य मानकर ने कहा दर्री टोला में मोबाइल क्रेशर को लेकर विधिवत सहमति नहीं देने के कारण सीलबंद किया गया। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्यारेलाल साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खनिज अधिकारी ने बताया कि दूसरे क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जा रही है। नागपुर और पौड़ी क्षेत्र में दो ट्रैक्टर रेत जब्त किया गया है। इसके अलावा मिट्टी ईंट के भट्टे पर भी कार्रवाई की गई। अवैध गिट्टी परिवहन करने वालों को भी पकड़ा गया है।

कलेक्टर ने भरारी केंद्र के खरीदी प्रभारी को हटाने के दिए निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मल्हार क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र प्रभारी जगजीवन कुर्रे को हटाने के निर्देश दिए। श्री कुर्रे के विरुद्ध धान खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही के कई आरोप लगे हैं। कलेक्टर ने बैठक में दलाल और बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी को संदेहास्पद लोगों की सूची पूर्व में दी गई है। ऐसे लोगों की हरकतों पर नजर रखें और तत्परता से कार्रवाई करें। वर्तमान कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य भी दिए। फड़ से उठाव में भी और तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। अब तक 37 फीसदी धान का समितियों से उठाव हो चुका है। कड़े निर्देश के बाद पिछले सप्ताह उठाव में तेजी आई है। कलेक्टर ने कहा कि धान बेच चुके किसानों का उनकी सहमति से रकबा समर्पण भी कराया जाए ताकि बिचौलिए इसका अनुचित लाभ न उठा पाएं।

कलेक्टर ने एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर हर एक समिति के हालात की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 3.68 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 78 हजार 557 किसानों ने अपनी निकट खरीदी केंद्रों में धान बेचा है। शासन की ओर से उन्हें 771 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। समिति स्तर पर भी छोटे किसानों को माइक्रो एटीएम के जरिए भुगतान किया जा रहा है। बिलासपुर सहित संभाग के 5144 किसानों को 4.76 करोड़ का भुगतान समिति से माइक्रो एटीएम से प्राप्त किया है। उन्हें राशि निकालने बैंक आने की जरूरत नहीं हुई। कलेक्टर ने कहा कि मौसम में बदलाव आया है । अगले दो-तीन दिन तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बताई गई है।

माओवादी देवा ने गोंदिया कलेक्टर व एएसपी के समक्ष किया आत्मसर्पण

राजनांदगांव। काफी लंबे समय बाद गोंदिया जिले में किसी नक्सली ने नक्सल पथ को छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। माओवादी संगठन में उत्पीडन और यातना से तंग आकर 7 लाख का ईनामी माओवादी देवा उर्फ अर्जुन उर्फ राकेश सुमदो मुदाम ने गोंदिया कलेक्टर प्रजीत नायर, गोंदिया एसपी गोरख भामरे एवं एएसपी नित्यानंद झा के समक्ष छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वालेने आत्मसमर्पण किया।। वह टांडा दलम सदस्य, मलाजखंड दलम, पामेड प्लाटून 9/ प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य है और राजनांदगांव रेंज के खैरागढ़ जिले में घटित अपराधों में शामिल होने नामजद रिपोर्ट दर्ज है।

माओवादी देवा का पैतृक गांव बीजापुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए उनके गांव में हमेशा वर्दीधारी हथियारबंद माओवादियों का आना-जाना लगा रहता है। माओवादियों के भ्रम और प्रलोभन में फंसकर वे बचपन से ही नक्सली आंदोलन में शामिल हो गए और उनके निर्देशानुसार बच्चों के संगठन में काम करने लगे, फिर 2014 में वे पामेड़ दलम दक्षिण बस्तर चले गए। वहां बीजापुर में भर्ती हुए और हथियार उठा लिया। 2014 के अंत में 6 महीने तक पामेड़ दलम में काम करने के बाद उन्होंने अबूझमाड़ इलाके में ढाई महीने तक ट्रेनिंग की। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें माओवादियों के क्षेत्र बस्तर से 2015 में एमएससी की उपाधि प्राप्त हुई और महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ जोन में भेजा गया।

एमएमसी में उन्होंने शुरूआत में 2015 से 2016 तक टांडा दलम और 2016 से 2017 तक मलाजखंड दलम में दलम सदस्य के रूप में काम किया। इसी बीच मलाजखंड क्षेत्र के डीवीसीएम चंदू उर्प देवचंद के अंगरक्षक के रूप में काम किया। 2018 में इसे वापस दक्षिण बस्तर इलाके में भेज दिया गया। 2018 से सितंबर 2019 तक माओवादी संगठन छोडने तक उन्होंने पामेड़ प्लाटून नंबर में सेवा की। 9वीं में प्लाटून दलम के सदस्य के रूप में कार्य किया।

आत्मसमर्पित नक्सली देवा 2014 से 2019 तक नक्सल संगठन में काम किया। वह टिपागढ़ फयरिंग (गढ़चिरौली), झिलमिली/काशीबहरा बकरकट्टा फायरिंग (राजनांदगांव), झिलमिली/मलौदा फारेस्ट कर्मचारी (राजनांदगांव), हत्तीगुड़ा/घोड़पाठ फारियंग (राजनांदगांव), किस्टाराम ब्लास्ट (सुकमा), पामेड़ फायरिंग (बीजापुर)। लेकिन मनमानी, फंड के नाम पर पैसे की लूट, झूठी लक्ष्य नीतियां, धोखा, प्रलोभन, नक्सली आंदोलन के नाम पर हिंसा का असली चेहरा सामने आने के बाद माओवादी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया।

सर्व आदिवासी समाज की मांग

बिना नोटिस आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगे रोक

बीजापुर। बीजापुर में बिना नोटिस के आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों पर होने वाली कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक और बीजापुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि बीते दिनों समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि जिले के चिन्नाकोड़ेपाल और दुगईगुड़ा पोर्टा केबिन आवासीय विद्यालय के प्रभारी अधीक्षकों को अव्यवस्थाओं के लिए दोषी मानते हुए एक तरफा कार्रवाई की गई है जोकि न्याय संगत नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों से बिना उनका पक्ष जाने और चेतावनी, नोटिस के बिना वेतन वृद्धि रोके जाने जैसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि यहां के आम जन मानस के समस्याओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान में सहभागी बनेंगे। इसके साथ ही जिले में अधिकारी कर्मचारी निर्भय होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

जग्गूराम तेलामी ने कहा कि बिना नोटिस आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगने की स्थिति में सड़क की लड़ाई के लिए समाज मजबूर होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जिला कलेक्टर ने दो गुंडा बदमाशों को किया जिलाबदर

दुर्ग। दुर्ग जिला कलेक्टर ने दो गुंडा बदमाश को जिलाबदर का आदेश जारी की है। जिसमे एक दुर्ग और एक भिलाई का रहने वाला है। जिसके खिलाफ कई थाना क्षेत्र में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों बदमाश दुर्ग - रायपुर के अलावा 5 अन्य जिलों सीमावर्ती में एक वर्ष के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। दो बदमाशों को जिलाबदर किया है। मोहम्मद इमरान और तेजिंदर उर्फ टोनी सरदार अदातन अपराधी हैं। जिनके कई अपराधिक रिकॉर्ड हैं। मो. इमरान इमामबाड़ा कैम्प दो शीतला मंदिर के पास थाना छावनी का रहने वाला है। वहीं, दूसरा अपराधी तेजिंदर उर्फ टोनी सरदार पचरीपारा गुरूद्वारा के पास संतराबाड़ी मोहन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों ही बदमाशों को एक वर्ष तक न केवल दुर्ग जिला ही नही बल्कि आसपास के सीमावर्ती 7 जिलों कि सीमाओं से भी बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। दोनों बदमाश दुर्ग के अलावा रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, धमतरी जिले के सीमावर्ती में बिना आदेश का प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।

प्रेमी जोड़े ने अपने ही घर को किया आग के हवाले

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में शुक्रवार की दोपहर लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़े के बीच उपजा विवाद उस समय बड़ी घटना में तब्दील हो गया जब उन्होंने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की इस घटना में घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बजरंग पारा अटल आवास में रहने वाले प्रेमी जोड़े के बीच शुक्रवार की दोपहर दो बजे के आसपास किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद उन्होंने अपने ही घर को आगे के हवाले कर दिया। इससे घर में रखा टीवी, फ्रिज, कूलर, राशन के अलावा घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अटल आवास के तीसरे फ्लोर में अचानक आग लगने की घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी की स्थिति हो गई। आगजनी की यह घटना विकराल रूप ले पाती उससे पहले ही पड़ोसियों ने फायर बिग्रेड की टीम को सूचना देते हुए स्वयं आग बुझाने की कोशिश की और तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया।

जंगल के भीतर पानी में मिली हाथी की लाश

कोरबा। कोरबा जिले में एक दंतैल हाथी की मौत से हड़कंप मच गया है। हाथी का शव पानी में मिला है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मौत की वजह करंट बताया जा है।मामला कोरबा वनमण्डल के कुदमुरा रेंज अंतर्गत गीतकुंवरी क्षेत्र का है जहां शनिवार की सुबह वन विभाग को हाथी की मौत के मामले की जानकारी मिली। हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई इस बात का अभी पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त ग्रामीण जंगल की ओर गए हुए थे इस दौरान अचानक हाथी पर नज़र पड़ी देखने के बाद मौके पर हड़कप मच गया है।वहीं देखते ही देखते ग्रामीणों के भीड़ एकत्रितहो गई। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई जहां मौके पर पहुंचे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए आगे की जांच कार्यवाही शुरू की जिस स्थान पर हाथी डूबा है वह नाला नुमा है और पानी ज्यादा नहीं है। वन विभाग की ओर से एसडीओ दक्षिण सूर्यकांत सोनी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के टीम मौके पर पहुंची हुई है।

अज्ञात बाइक चालक ने अधेड़ ग्रामीण को मारी टक्कर

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में छठी कार्यक्रम से पैदल घर लौट रहे अधेड़ ग्रामीण को अज्ञात बाइक चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। इस दुर्घटना में घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे की शिकायत पर लैलूंगा ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खार गांव निवासी हिमांशु भगत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कल उसके पिता बालक राम भगत, छोटी बहन कुसूम भगत एवं भतीजा संजू भगत के साथ छठी निमंत्रण पर बगईझराई पारा गए हुए थे। वहां से शाम करीब 6 बजे के आसपास जब तीनों पैदल घर आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम खुसरमुडा कांक्रेटिंग मार्ग के पास अज्ञात बाइक चालक ने बालक राम भगत को पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में बालक राम भगत के चेहरे, माथा, सिर में चोंट लगी। ग्रामीणों ने परिजनों को इस घटना से अवगत कराया।

कांकेर में सड़क दुर्घटना में दो युवतियों समेत पांच की मौत

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की चपेट में आने से मोटरसाइकिलों पर सवार दो युवतियों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र के अंतर्गत खंडी नदी के करीब एक स्कॉर्पियो वाहन ने दो मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिलों पर सवार दो युवतियों कामती कावड़े, प्रियंका निषाद और तीन युवकों सेवन कुमार, चोकेश्वर प्रजापति और एक अन्य की मौत हो गई। सभी मृतकों की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ की ओर जा रहा एसयूवी आज जब खंडी नदी के करीब पहुंचा तब उसने सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिलों पर सवार दो युवतियों और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

माफियाओं के लिए जमीन से कब्जा खाली कराने वाला गैंग गिरफ्तार

■ बाइक लूटने के बाद गिरोह का भंडाफोड़

सरगुजा। अंबिकापुर में जमीन से कब्जा खाली कराने वाले गैंग को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अंबिकापुर में हरियाणा के गुर्गे जमीन पर कब्जा खाली कराने का काम करते थे। सीतापुर इलाके में बाइक लूट के बाद गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

अमोलक सिंह ढिल्लो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह गिरोह जमीन माफियाओं के लिए अंबिकापुर में काम करने का प्लान बनाया था। सीतापुर इलाके में बाइक लूट के बाद गिरोह को पकड़ा गया है। ठेकेदार मनीष अग्रवाल के कर्मचारी की बाइक को गिरोह ने लूटा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। आरोपी बाइक लूट के बाद फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गांधीनगर क्षेत्र के सुभाषनगर से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह से एक कट्टा, डंडा, स्कॉर्पियो व बाइक जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की थी इसलिए ष्ट्त नंबर की बाइक लूटे थे, ताकि लोगों को स्थानीय नंबर की बाइक पर घूमने से शक न हो।

2 महीने से केशकाल घाट बंद, आवाजाही बंद होने से छोटे व्यापारी परेशान

कांकेर। बस्तर के केशकाल घाट में नवीनीकरण कार्य बीते 2 माह से जारी है, 2 जनवरी तक बड़ी वाहनों के लिए घाट बंद रहेंगे। ऐसे में बीते दो महीने से भारी वाहनों के आवाजाही बंद होने से ढाबे वीरान हो गए हैं। साथ ही छोटे व्यपारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, इस क्षेत्र में भारी वाहनों की वजह से कई ढाबे संचालित होते हैं, जिनकी आजीविका इन्हीं पर निर्भर है। केशकाल घाट के नवीनीकरण में देरी से ढाबा संचालकों की परेशानी बढ़ गई है।

ढाबा संचालकों का कहना है कि जहां रोजाना 60 से 70 ट्रक रुका करती थी , वहां 2 माह से एक भी ट्रक नहीं आ रही है। ऐसे में ढाबा में काम करने वाले कर्मचारियों को मजदूरी देने तक के पैसे नहीं बच रहे है। कुछ ढाबा संचालकों ने तो ढाबा ही बंद कर दिया है। उनका कहना है कि दिन भर में एक दो ग्राहक आ रहे थे, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ रहा था।

वहीं नेशनल हाइव के किराने, पंचर, चाय की दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारी भी काफी परेशान है। उनका कहना है कि ट्रकें चलने से ही उनका जीवनयापन चलता है। दो माह से इस मार्ग से ट्रकों के नहीं गुजरने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। पहले जहां रोजाना 1 से 2 हजार तक की कमाई होती थी। अब दिन भर में 200 रुपए की कमाई नहीं हो पा रही है।

जानवरों के चमड़े से भरे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त

■ महाराष्ट्र से कोलकाता जाते समय कार्रवाई

दुर्ग। दुर्ग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानवरों के चमड़े से भरा एक ट्रक जप्त किया है। कुम्हारी टोल प्लाजा के पास कुम्हारी पुलिस और गौसेवकों ने मिलकर यह संयुक्त कार्रवाई की है। ट्रक महाराष्ट्र से कोलकाता जा रहा था। ट्रक में गौवंश का चमड़ा लोड था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने ट्रक को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर रही है।

छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि गौसेवक और यातायात पुलिस महाराष्ट्र से कोलकाता जा रहा था इस ट्रक को राजनांदगांव से पीछा कर रहे थे। इस दौरान कुम्हारी थाना पुलिस को भी जानकारी दी गई। जिसके बाद कुम्हारी टोल प्लाजा में ट्रक को रुकवाकर तलाशी देने पर गौवंश का चमड़ा लोड था। पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। किया है।

फिलहाल पुलिस चमड़े से भरे इस ट्रक को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक में गोवंश के साथ अन्य जानवरों के भी चमड़े है। जिसकी जांच कराई जा रही है।ट्रक चालक ने पुलिस को बताया है कि महाराष्ट्र के अमरावती से कोलकाता के किसी फैक्ट्री में लेकर जा रहे थे। वही गौसेवको और अन्य लोगो ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई भी की है।

कवासी लखमा और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

■ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। मीडिया के मुताबिक राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत यह छापेमारी की गई है।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुल सात ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनमें रायपुर में लखमा का आवास और सुकमा जिले में उनके बेटे हरीश लखमा का आवास शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी शहरी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है। 71 वर्षीय लखमा कोंटा विधानसभा सीट से छह बार विधायक रह चुके हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। हरीश लखमा अपने जिले में पंचायत अध्यक्ष बताए जाते हैं।

2020-2022 में कवासी लखमा के मंत्री रहने के दौरान लखमा को दो करोड़ रुपये हर महीने के भुगतान का आरोप लगा था जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। कथित शराब घोटाला 2019-22 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत किया गया था जिसके तहत खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अवैध आय से भर गईं।

वहीं इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विंग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि राज्य

में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की भाजपा की साजिश है।

दो कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी नगर पालिका अध्यक्ष के घर भी दबिश

भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छापा मारा है। ईडी की टीम ने रायपुर और बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में दबिश दी है। भूपेश सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा के रायपुर स्थित धरमपुरा घर में और उनके बेटे हरीश लखमा के सुकमा स्थित आवास पर छापेमारी की है। वहीं सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम दो वाहनों में सवार होकर कांग्रेस नेताओं के घर पहुंची है। इस टीम में करीब 8 अधिकारी शामिल हैं।

वहीं नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के आवास पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जवान घर पर तैनात हैं। रायपुर में पूर्व मंत्री लखमा के घर में ईडी की टीम जांच-पड़ताल कर रही है। यहां भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं।

दूसरी ओर एनआईए ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में नक्सली मामलों की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि टीमों ने संदिग्धों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के घरों और अन्य जगहों की गहन तलाशी ली, जिसमें कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए।

इसके साथ ही एनआईए की टीमों ने छत्तीसगढ़ के दूरदराज के गांवों में भी तलाशी ली। ये तलाशी पिछले साल राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान और सुरक्षा दल पर सीपीआई (माओवादी) के हमले से संबंधित थीं। जहां एनआईए ने गरियाबंद और धमतरी जिलों के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में रावनडिग्गी, सेमरा, मैनपुर, घोरागांव, केराबहरा और गरियाबंद के गांवों में 11 संदिग्धों के घरों और अन्य स्थानों पर तलाशी ली। जहां जांच में यह पाया गया कि संदिग्धों के ओजीडब्ल्यू और सीपीआई (माओवादी) के समर्थक होने का अनुमान है।

एनआईए ने बताया कि इन संदिग्धों के परिसरों से नक्सली पर्चे, पुस्तिकाएं, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, 1.5 लाख रुपये नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। अब तक इस मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

संक्षिप्त समाचार

छग के कांग्रेसजन आज देंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि

रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन शंकर नगर की सुबह 11:45 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने प्रदेश एवं रायपुर शहर में निवासरत प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के सदस्य, वरिष्ठजन, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक,पार्षद, पूर्व पार्षद,समस्त प्रदेश पदाधिकारी, शहर एवं ब्लॉक पदाधिकारी, वार्ड पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित सदस्यगण, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सदस्यगण,युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, किसान काग्रेस, असंगठित क्षेत्र जनसमस्या निवारण प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग,पिछड़ा वर्ग विभाग,झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, बुथ अध्यक्ष,सेक्टर अध्यक्ष,जोन अध्यक्ष एवं सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के सम्मानीयजन के साथ समस्त कांग्रेसजनों से श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहने की अपील की है।

टी.एस. सिंहदेव ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर अर्पित की श्रद्धांजलि

नई दिल्ली-रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह की पुत्री से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। सिंहदेव ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह जी का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए अविस्मरणीय है। उनका सरल स्वभाव, कुशल नेतृत्व और देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास हमेशा याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण के साथ सूचना का अधिकार,नरेगा शिक्षा का अधिकार,परमाणु संधि,किसानो की ऋण माफ़ी जैसे अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश हित में किए उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और अपनी नीतियों से करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। डॉ. मनमोहन सिंह के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए श्री सिंहदेव ने उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

स्मृति मंदिर में दी गई कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि

रायपुर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर के स्मृति मंदिर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

नशे के सौदागरों से गहरे संबंध रखने के आरोप में 4 पुलिस कर्मी निलंबित

दुर्ग। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, अगर वही उनके साथ जाए तो क्या हो? ऐसा ही एक मामला दुर्ग में सामने आया जहां मोहन नगर और स्मृति नगर के प्रधान आरक्षक और आरक्षक मिलकर नशे के सौदागरों से मिले हुए थे। इसकी जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने चारों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन के साथ ही दुर्ग नगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश देते हुए कहा कि वह इस मामले की संपूर्ण जांच एक सप्ताह के भीतर पूरी कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निलंबन की अवधि में नियमानुसार इन पुलिस कर्मियों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों में प्रधान आरक्षक शाहिद खान - मोहन नगर थाना, आरक्षक बेदराम बंदे - स्मृति नगर थाना, आरक्षक तारकेश्वर साहू और आरक्षक संतोष सोनी शामिल है।

सट्टा-पट्टी लिखते दिलेश्वर गिरफ्तार

रायगढ़। भगवानपुर सीएमओ तिराहा के पास सट्टा-पट्टी लिखते हुए कोतरारोड थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस ने रामभाठा के रहने वाले दिलेश्वर भारती को गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा पर्ची, पेन और 2,270 रुपये नगद बरामद किया। जब्त की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने भगवानपुर तिराहा पर दबिश दिया जहां सट्टा-पट्टी लिखते हुए आरोपी दिलेश्वर भारती (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया।

नक्सलियों द्वारा लगाये गये 20-20 किलो के 2 आईईडी बरामद

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना पोलमपल्ली से सीआरपीएफ के के जवान सर्चिंग पर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से दोरनापाल-जगरगुंडा जाने वाली मार्ग के पास नक्सलियों द्वारा लगाये गये 20-20 किलो का 2 नग कमांड आईईडी को सुरक्षित तरीके से बरामद कर सीआरपीएफ के जवानों ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया है।

राज्यपाल रमेन डेका से राज्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्त श्री अजय सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने नगरीय एवं पंचायत निर्वाचन की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अम्बेडकर अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा प्रारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट सर्जरी विभाग के कुशल डॉक्टरों की टीम ने 50 वर्षीय महिला की सफल ओपन हार्ट सर्जरी कर मरीज को नया जीवन दिया है। हार्ट सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में यह सफल ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के बाद महिला की हालत ठीक है तथा वह अभी डॉक्टरों की देखरेख में है।

मरीज का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य के निवासियों को नए वर्ष के आगमन पर ओपन हार्ट सर्जरी सुविधा की शुरुआत के लिए अस्पताल प्रबंधन को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। जायसवाल ने कहा है कि बहुत जल्द ही यहां बाईपास सर्जरी की शुरुआत भी होगी। महासमुंद निवासी 50 वर्षीय महिला मरीज को लगभग तीन साल से सांस फूलने की शिकायत थी। थोड़ा भी काम करने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती थी जिसे हार्ट पल्पिटेशन कहा जाता है। अपनी इन्हीं समस्याओं के साथ महिला अम्बेडकर अस्पताल के एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट के हार्ट सर्जरी विभाग में डॉ. कृष्णकांत साहू के पास पहुंची। उन्होंने मरीज की पूरी जांच की।

जाँच में पता चला कि हार्ट के वाल्व में सिकुड़न है और एक वाल्व में लीकेज है। हार्ट का वाल्व इतना सिकुड़ गया था कि इनको डॉक्टर ने 3 साल पहले ही ऑपरेशन की सलाह दी थी मगर ओपन हार्ट सर्जरी का नाम सुनकर मरीज तथा उसके परिवार के लोग घबरा गए और उस वक्त उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी करवाने

से मना कर दिया फिर उसके बाद समस्या बढ़ती गई और मरीज पुनः एक बार फिर डॉ. कृष्णकांत साहू के पास पहुंची, जहां पर उन्होंने ने महिला को ओपन हार्ट सर्जरी से संबंधित सभी जानकारी दी। उनकी काउंसलिंग की। सर्जरी के पश्चात स्वास्थ्य में होने वाले सुधार के बारे में विस्तार से बताया।

डॉ. कृष्णकांत साहू ने मरीज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर को केस की गंभीरता तथा ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के निर्देश पर तत्काल कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूजनिस्ट तथा अन्य मानव संसाधन की व्यवस्था की गई । अंततः 26 दिसंबर को मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी की गई तथा मरीज के हृदय में कृत्रिम वाल्व का प्रत्यारोपण किया और एक वाल्व को रिपेयर किया।

इस ऑपरेशन को मेडिकल भाषा में माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग बाईलीफलेट मैटेलिक प्रोस्थेटिक वाल्व प्लस ट्राईकस्पिड वाल्व रिपेयर अंडर हार्टलंग मशीन कहा जाता है।

बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। भले ही इन शिक्षकों की नौकरी पर संकट तकनीकी रूप से अदालती निर्णय के कारण आया है लेकिन सरकार चाहे तो इस समस्या का तत्काल निराकरण कर सकती है। सरकार के पास शिक्षा विभाग में ही अनेकों ऐसे पद है जहां समान वेतनमान पर इन 2897 शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी शिक्षकों के रूप में इनकी नियुक्तियां की जा सकती है। वर्तमान शिक्षा विभाग में 70 हजार पद रिक्त है। 33000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सरकार रोक कर रखी हैं।

इन पदों पर इन शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है। सरकार इनके मामले में तत्काल निर्णय लेकर इनका समायोजन करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 2897 सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिये आंदोलनरत है, धरने पर बैठे है सरकार है कि इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले रही है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने सरकार के पास अनेकों विकल्प है, विभागीय डीएड परीक्षा का आयोजन भी करवा कर नौकरी यथावत बरकरार रख सकती है सरकार लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। भाजपा सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है। इन शिक्षकों को सरकार ने भर्ती निकाल कर प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति दिया था।

अब अदालत के निर्णय के बाद गतिरोध आ रहा है तो सरकार इस मामले का समाधान निकाल डीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये अलग भर्ती निकाले तथा इन पहले से नियुक्ति पा चुके 2897 शिक्षकों की सेवा आगे सुनिश्चित रखने की व्यवस्था करें। इन शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ था, ऐसा नहीं है भाजपा सरकार बनने के बाद भी तीसरी और चौथी काउंसलिंग 9 फरवरी 2024 तथा 7 मार्च 2024 को हुई थी तथा इनकी नियुक्तियां हुई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस मामले में प्रभावित अधिसंख्यक शिक्षक बस्तर और सरगुजा संभाग के है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ है।

मुद्रा योजना की बदौलत खड़ा किया अपना डेयरी का व्यवसाय

अम्बिकापुर। नीतू चंवर अम्बिकापुर के ठनगनपारा में अपने दो बच्चों के साथ रहती हैं। कभी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली नीतू की जिंदगी आज खुशियों से भर गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर नीतू ने डेयरी का व्यवसाय शुरू किया है और आर्थिक रूप से सशक्त हुईं। बीते सालों को याद करते हुए नीतू अपनी आपबीती बताते हुए कहतीं हैं, जो संकट का समय मैंने देखा है, वो किसी के जीवन में ना आए। उन्होंने बताया कि तीन साल पहले उनके पति का निधन हो गया। पति टेलरिंग का कार्य करते थे, जिससे रोजी-रोटी चलती थी। दो बच्चों की परवरिश, उनके पढ़ाई-लिखाई सबका खर्च, इसी काम से चल रहा था। पति का निधन हमारे जीवन में दुःखों के पहाड़ की तरह था। एक तो बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ जाना और ऊपर से परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति का चले जाना। ऐसे में मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों का पालन-पोषण और उनका भविष्य था, उनके भविष्य की चिंता मुझे सताने लगी। तब मैंने स्वयं कुछ काम करने का सोचा, लेकिन

कुछ समझ नही आ रहा था कि कहा से और कैसे शुरू करूँ। क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत थी, जो बचत थी, वो भी खत्म हो गई थी। ऐसे में मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला। मैंने आवेदन किया, मुझे 25 हजार का लोन मिला। लोन मिलने के बाद मैंने एक गाय ख़रीदी और डेयरी का व्यवसाय शुरू किया।

डेयरी का व्यवसाय शुरू करने के बाद नीतू को दूध बेचकर अच्छी कमाई होने लगी। जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती गई, नीतू ने और गाय खरीदी। आज उनके पास कुल 08 गाय हैं, जिससे नीतू रोजाना 60 लीटर दूध बेचतीं हैं। नीतू को महीने में लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। गाय की देखभाल, चारा आदि के बाद भी के अच्छी खासी राशि की बचत हो जाती है। नीतू की बड़ी बेटी रेणु एमए की पढ़ाई कर रहीं हैं। रेणु बताती हैं कि पिता के निधन के बाद हमारा परिवार बिखर गया।

भाजपा संगठन में महिलाओं को मिलेगी जिम्मेदारी: साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति विवाद के बीच बड़ी बैठक की गई, इसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल हुए। इसे लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंडल अध्यक्षों का अच्छे से चुनाव संपन्न हुआ है। 400 से ज्यादा मंडल है, एक दो में शिकायत आई है। जिला अध्यक्षों के चयन में बहुत अच्छे से राय सुमारी हुई है। तीन नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीजेपी ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है। राजनीति में भागीदारी महिलाओं की हो इस दिशा में बीजेपी काम करती है। मंडल अध्यक्षों के बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव में

महिलाओं को जिम्मेदारी मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नियमित रूप से जनसंपर्क जाता हूं। ये देखने कि लगातार क्षेत्र में विकास हो रहा है या नहीं। हम आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं।

रायपुर के शारदा चौक सड़क चौड़ीकरण को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लगातार उस दिशा में काम हो रहा हैं। आने वाले समय में विकास के जितने भी काम है। वह तेजी से होंगे।

जल जीवन मिशन में हो रहे कामों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होनें कहा कि जल जीवन मिशन का काम ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन योजना है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप जल पहुंच सके। हमारी सरकार लगातार इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से कम कर रही है।

माँ बागेश्वरी मंदिर कुदरगढ़ के विकास के लिए मंत्री राजवाड़े ने सचिव छत्तीसगढ़ को

रायपुर। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ स्थित माँ बागेश्वरी मंदिर के कायाकल्प और सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार को पुनः स्मरण पत्र जारी की है।

गौरतलब है कि प्रसाद योजना, भारत सरकार की एक योजना है जिसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान योजना के तहत, तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उन्हें पहचान दिलाने पर ध्यान दिया जाता है। प्रसाद योजना के तहत पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए इसे 'प्रसाद' योजना में शामिल किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन में विधानसभा भटगावँ में माँ बागेश्वरी धाम में रोप वे, हेलीपेड, यज्ञ शाला, ज्योति कक्ष, सीढ़ी निर्माण, यात्री शेड, हाई मास्क लाइट, सी.सी.टी.वी., पेयजल, सेस्क्युरिटी चेक पॉइन्ट, शौचालय, हर्बल गार्डन, हाट-बाजार, अपशिष्ट प्रबंधन, यात्रियों की सुविधा हेतु बैटरी चलित वाहन, स्टॉप डेम विकास, प्रसाद किचन, प्रतीक्षालय आदि विकास कार्यों को सम्पन्न किये जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर लाल पटवा की पुण्यतिथि तथा अरुण जेटली की जयंती पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 28 दिसंबर को स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे और श्री सुंदर लाल पटवा की पुण्य तिथि तथा श्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें नमन किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कुशाभाऊ ठाकरे जी के देश के लिए योगदान को याद करते हुए कहा है कि कुशाभाऊ जी नैतिकता, आदर्श व सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ थे। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अटूट था। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग की सुख-समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे निष्काम कर्मयोगी के विचार और जीवनमूल्य हमें सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पद्मविभूषण स्वर्गीय श्री अरूण जेटली

की 28 दिसंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि जेटली जी ने भारत के वित्त, रक्षा, कॉरपोरेट मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को कुशलता से संभाला और देश के विकास को नई गति दी। उन्होंने देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेटली जी को वित्तीय मामलों का गूढ़ जानकार माना जाता था। उन्होंने भारत में आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अरुण जेटली जी का देश के विकास में दिया गया अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

इसी तरह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री पद्म विभूषण श्री सुन्दर लाल पटवा की 28 दिसंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि पटवा जी अनुशासनप्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। सौम्य व्यक्तित्व, कुशल संगठन क्षमता से युक्त, ओजस्वी वक्ता और विभिन्न जनसमस्याओं को उठाने वाले जुझारू नेता के रूप में पटवा जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई।

उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया और किसान हितैषी कई फैसले लिए। वे सहकारी आंदोलन से जुड़े और अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को संभाला। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को जनोन्मुखी बनाया। उनके कार्यकाल में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों, शिल्पियों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के सफल प्रयोग किये गये। श्री साय ने कहा कि पटवा जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें सदैव अपने दायित्वों का उत्कृष्टतापूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा देता रहेगा।

निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

रायपुर। नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 में मतदाता बनाने के लिए कार्यक्रमों में संषोधन किया गया है। नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और अवसर प्राप्त हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को की जाएगी।

छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 06 जनवरी 2025 सोमवार 3 बजे तक दावे/आपत्तियों का निपटारा 09 जनवरी 2025 गुरूवार किया जाएगा। नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी तय की गई है। ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भी मतदाता बनने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगे। इस तरह नई मतदाता सूची तैयार होने के बाद ही नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली प्रारूप क-1 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी का दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक और प्रारूप क-1 में प्राप्त आवेदनों का निराकरण की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 निधारित की गई है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को की जाएगी।

अंतरिम सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा

अवधेश कुमार

बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम यूनुस सरकार ने स्वीकार किया है कि शेख हसीना सरकार के जाने के बाद अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हुई हैं। किंतु इसमें भी मोटा-मोटा उन्होंने उन घटनाओं को स्वीकार किया है जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में है। कहा है कि ऐसी 88 घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी घटनाएं बहुत कम हुईं और इनमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाइयां की हैं। हालांकि भारत की ओर से इसे उठाने के बावजूद हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले दिनों मैमन सिंह और दिनाजपुर जिले में आठ देव प्रतिमाओं को खंडित किया गया और पुलिस ने इनकी पुष्टि की है। हिंदुओं के श्मशान घाट तक सुरक्षित नहीं हैं। नाटोर के कासिमपुर सैंट्रल श्मशान घाट के मंदिर के पुजारी की हत्या का भी समाचार आया है। पुजारी की हत्या के बाद लूटपाट हुई और पुलिस इसे डकैती बता रही है। अंतरिम सरकार से बंगलादेश नहीं संभल रहा है या वह हिंदुओं पर हमले को रोकना नहीं चाहती क्योंकि जिस तरह अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों को लगातार इस्लामी कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं उसका क्या निष्कर्ष हो सकता है। बंगलादेश का लगातार स्टैंड है कि भारत बातें बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहा है। भारत को उत्तेजित करने जैसे आधारहीन आरोप तक यूनुस सरकार लगा रही है। अंतरिम सरकार द्वारा वहां के सेवानिवृत न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट बंगलादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफैसर मोहम्मद यूनुस को सौंपी जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में जबरन लोगों को गायब करने की घटनाओं में भारत संलिप्त था। विरोधी शेख हसीना पर लोगों को गायब करने का आरोप लगाते रहे हैं और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'अनफोल्डिंग द ट्रूथ ' में इनकी संख्या करीब 3000 बताई है। यहां तक कह दिया है कि बंगलादेश के कुछ कैदी अभी भारत की जेल में हो सकते हैं। जरा सोचिए, हम भारतीयों के पाकिस्तान की जेल में बंद होने की बात करते रहे हैं और अब बंगलादेश आरोप लगा रहा है कि शेख हसीना के साथ लोगों को गायब कर जेल में रखने का अपराध भारत ने किया है। भारत सरकार, चाहे वहां हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों की सुरक्षा के लिए जितनी आवाज उठाए या संयम दिखाए बंगलादेश के वर्तमान सत्ताधीश हर स्तर पर भारत को आरोपित करने और उसे उत्तेजित करने की कोशिश जारी रखने वाला है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बंगलादेश की यात्रा पर गए थे। उन्होंने संसद की स्थायी समिति के समक्ष पूरी बात रखी। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन जैसा स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बताया कि बंगलादेश की अंतरिम सरकार ने अपने देश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। भारत एक गंभीर और परिपक्व देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को भान है कि किसी आक्रामक प्रत्युत्तर और वक्तव्य का वहां के हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए अत्यंत संयत रवैया अपनाया जा रहा है। विक्रम मिस्री ने बंगलादेश की यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की। वस्तुत: अगस्त में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फैंके जाने के बाद भारत के किसी उच्च अधिकारी की पहली यात्रा थी। राजधानी दिल्ली सहित भारत के प्रमुख स्थानों पर लगातार बंगलादेश के हिंदुओं पर हिंसा के विरुद्ध स्वत:स्फूर्त प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें लोगों का क्रोध साफ दिखाई देता है। एक सीमा तक यह बंगलादेश का आंतरिक मामला है लेकिन हर देश की जिम्मेवारी अल्पसंख्यक नागरिकों को उनके धार्मिक पहचान के साथ जान-माल की रक्षा करने की है। अगर कोई देश इस जिम्मेदारी का पालन नहीं करता तो क्या किया जाए? बंगलादेश में हिंदुओं और उनसे जुड़े स्थलों पर हमले के विरुद्ध दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमरीका में भी भारतीयों ने 'हमें न्याय चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करो' का नारा लगाते हुए व्हाइट हाऊस से लेकर पूरी राजधानी में प्रदर्शन किया।

संविधान, आरक्षण और अंबडेकर पर कांग्रेस बेनकाब

मृत्युंजय दीक्षित

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ समाप्त हो चुका है। अपनी आदत के अनुसार विपक्ष विरोध के नाम पर सदन से भी सियासी चिंगारी निकालने का प्रयास कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संविधान पर चर्चा का आयोजन किया गया था जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संविधान पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में संविधान, आरक्षण और डॉ. आंबेडकर पर कांग्रेस के विचारों को सप्रमाण सदन में रखा जिससे निरुत्तर हुई कांग्रेस ने राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन से 12 सेकेंड का एक टुकड़ा उठाकर उसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए गृहमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस झूठे विमर्श को सच सिद्ध करने के प्रयास में पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर एकजुट हो रहा है।

यद्यपि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप और कांग्रेस आमने सामने हैं किन्तु आप के नेता भी गृहमंत्री की कथित टिप्पणी का वीडियो बनाकर गली-गली में घुमा रहे हैं कि शायद इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिल जाए। गृहमंत्री के विरुद्ध उसी प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा जैसा 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को आरक्षण विरोधी व संविधान विरोधी साबित करने के लिए किया गया था। अब हर एक दल व नेता डॉ. आंबेडकर को भगवान बनाकर अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को पार लगाने का स्वप्न देखने लगा है। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के अगले दिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दलितों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए संसद परिसर में नीली टी शर्ट और नीली साड़ी पहनकर नमूदार हुए। उप्र में समाजवादी पार्टी भी भला पीछे क्यों रहती उसने भी डॉ. आंबेडकर की तस्वीरों के साथ यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा किया ओर सदन की कार्यवाही ठप करने का प्रयास किया।

गृहमंत्री के बयान के खिलाफ विपक्ष देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में बसपा नेत्री मायावती ने भी आक्रामक तेवर अपनाए हैं किन्तु वह सधे हुए बयान देकर कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों ही दलों को नसीहत दे रही हैं। बसपा नेत्री मायावती कांग्रेस पर हमलावर हैं, उनका कहना है कि बाबा साहेब की उपेक्षा करने वाली और देशहित में उनके द्वारा किये गये संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का बाबा साहेब के अपमान को लेकर उतावालापन विशुद्ध छलावा है। बहिन मायावती ने डॉ. आंबेडकर के प्रति प्रेम दर्शा रहे समाजवादियों की पोल भी खोलकर रख दी है, मायावती का मानना है कि आज सपाई बाबासाहेब के नाम पर पीडीए का पर्चा निकाल रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि सपा ने भी कभी भी डॉ. आंबेडकर का सम्मान नहीं किया था। समाजवादियों ने वास्तव में बाबा साहब सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के प्रति द्वेष के तहत नए जिले, नई संस्थाओं व जनहित योजनाओं तक के नाम बदल डाले थे। सपा सरकार में तो डॉ. आंबेडकर का नाम तक सही नहीं लिखा जाता था।

कांग्रेस पार्टी आज नीली टी शर्ट व नीली साड़ी पहनकर इतराती हुई घूम रही है और उसे लग रहा है कि उसे वह मुद्दा मिल गया है जिससे उसकी वापसी की राह आसान हो जायेगी लेकिन कांग्रेस बहुत बड़े भ्रम में है। सभी जानते हैं यह वहीं कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी डॉ. आंबेडकर का सम्मान नहीं किया और न ही संविधान का कभी मान रखा। आज कांग्रेस नीले कपड़े पहनकर दलित समाज को छलने के लिए निकल पड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉ. आंबेडकर का सम्मान किया होता तो आज उसकी यह दुर्गति न होती।

स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही कांग्रेस और डॉ. आंबेडकर के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गये थे। कांग्रेस के साथ बाबासाहेब का प्रथम विवाद 1930 में गोलमेज कांफ्रेंस के समय हुआ था। आंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे जबकि गांधी जी इसके विरोधी थे। गांधी जी ने आंबेडकर जी के खिलाफ आमरण अनशन तक किया था। 29 जनवरी 1932 को दूसरी गोलमेज सम्मेलन के बाद मुंबई में बाबा साहब ने कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही कहते हैं, यानी आज जो बाबासाहब की फोटो लेकर राजनीति कर रहे हैं,उस समय उन्हें गद्दार कहते थे। संविधान सभा में आंबेडकर जी के चयन का रास्ता भी नेहरू जी ने ही रोका था। हिंदू कोड बिल और सरकार की दलित विरोधी मानकिता के चलते आंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए लिखा, संरक्षण की सबसे अधिक जरूरत अनुसूचित जाति को है पर नेहरू का सारा ध्यान सिर्फ मुसलमानों पर है। ध्यान देने योग्य बात है कि आज भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुस्लिम परस्त है।

कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आंबेडकर जी का लगातार अपमान करती रही। बाबा साहब को 40 साल तक भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा जबकि कांग्रेस अपने ही परिवार को भारत रत्न देती रही। नई दिल्ली में गांधी नेहरू परिवार की पीढ़ियों के स्मारक बने हैं जबकि गांधी परिवार ने आंबेडकर जी का अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नही होने दिया। कांग्रेस ने पग-पग पर डॉ. आंबेडकर के विचारों का धुर विरोध किया और आज राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर उनके अपमान पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वस्तुत: कांग्रेस का आंबेडकर के प्रति प्रेम 2019 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से उमड़ा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस व विरोधी दलों के सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह सपने में भी डॉ.आंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। संसद में चर्चा के दौरान यह तो सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने न केवल जीते जी बाबा साहेब का लगातार अपमान किया वरन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहेब का एक भी स्मारक नहीं बना जबकि जहां -जहां अन्य दलों की सरकारें आती गई वहां -वहां उनका स्मारक बनता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबासाहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ विकसित किये। जिसमें मध्य प्रदेश में महू, लंदन में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि का विकास किया। 19 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने डॉ. आंबेडकर के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। आज जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं यही लोग संविधान दिवस का विरोध व बहिष्कार करते रहे हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व में आज संपूर्ण विपक्ष केवल वोटबैंक की राजनीति के कारण ही सदन में डॉ. आंबेडकर के अपमान का मुद्दा उछाल रहा है, क्योंकि देश में 20 करोड़ 13 लाख 78 हजार 86 दलित हैं जो आबादी का 16.63 फीसदी है। दलितो की आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 23.6 फीसदी है। इस आबादी को अपना वोट बैंक बनाने के लिए आतुर कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर रोज नए नए स्टंट कर रही है क्योंकिउसको लगता है कि अकेले मुस्लिम वोट बैंक से उसे सत्ता नहीं मिल सकती।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

महाभारत में भी युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय यवन देश के राजाओं का आना लिखा है यथा- प्राग्ज्योतिषाधिप: शूरो म्लेच्छानामधिपो बली । यवनै: सहितो राजा भगदत्तो महारथ:।। (महाभारत सभापर्व 51 ।3-26)

अर्थात्- प्राग्ज्योषित (Assam) देश का अधिपति शूरवीर म्लेच्छराज महारथी भगदत्त भी यवनों सहित (राज्याभिषेक में) सम्मिलित हुआ। महाभारत के संग्राम में भी यवन लोग आये थे और श्रीकृष्ण जी के साथ कालयवन का युद्ध तो सर्वविदित बात है। इसी प्रकार कविश्रेष्ठ कालीदास ने भी महाराजा रघु की दिग्विजय का वर्णन करते हुये रघुवंश में नीचे लिखा श्लोक दिया है- यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न स:। (रघुवंश 4 ।31)

अर्थात्- इस रघु ने यवन देश की स्त्रियों के मुखपद्मों से उठने वाली शराब की गन्ध को सहन नहीं किया, यानी विलासी यवनों को परास्त कर दिया। दयानन्द जी ने भी सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में साफ लिखा है कि- सवन जिसको यूनान कहु आये, और ईरान का शल्य आदि सब राजा राज्यसूय यज्ञ और महाभारत के युद्ध में आज्ञानुसार आये थे।

इत्यादि अनेक प्रमाणो से जाना जाता है कि यवन शब्द का अर्थ मुहम्मद-मतानुयायी मुसलमान नहीं, बल्कि प्रसिद्ध यूनान देशवासी है। जैसे भारतनिवासी पुरुषों को सदा से भारतीय कहते हैं इसी भान्ति यूनान देश के निवासियों को यवन कहा जाता है। प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है, कि यद्यपि कल तक भारतीय सम्राटों का ही सर्वाधिपत्य रहा है, तथापि बीच 2 में अन्यान्य देशवासियों ने भी भारत पर आक्रमण करने में कोर कसर बाकी न रखी थी। भगवती दुर्गा का योरुपीन बिडालाक्ष के साथ घोर घमसान युद्ध हुआ था यह प्राय: सबको विदित है।

क्रमश: ...

रामानंद सागर

अनन्या मिश्रा

मायथोलॉजिकल शो में रामानंद सागर के रामायण सीरियल की बराबरी आज भी नहीं है। आज भी लोग 80 के दशक के इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं। इस सीरियल को बनाने के वाले रामानंद सागर की प्रतिभा का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह डायरेक्टर होने के साथ स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, उम्दा लेखक और प्रोड्यूसर भी थे।

पाकिस्तान के लाहौर में 29 दिसंबर 1917 को रामानंद सागर का जन्म हुआ था। इनका असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। वहीं इनकी नानी ने इन्हें रामानंद नाम दिया था। देश के बंटवारे के बाद रामानंद का परिवार भारत आ गया। उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में परिवार की मदद के लिए रामानंद ने कम उम्र से काम करना शुरूकर दिया था। वहीं यह भी कहा जाता है कि उन्होंने चपरासी और ट्रक क्लीनर की नौकरी भी की थी। मामा के घर में होने के बावजूद रामानंद का बचपन दर्द में गुजरा। हालांकि पूरी बातों का आजतक किसी को पता नहीं चला है। रामानंद सागर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो दिन-रात पढ़ने में लगे रहते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब- प्रीतम प्रतीक्षा लिखी। ये वो दौर था जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काम भी किया करते थे।

थोड़े समय बाद रामानंद सागर मुंबई आ गए और उन्होंने बतौर राइटर अपने करियर की शुरूआत की। वह कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा करते थे। जल्द ही वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वहीं साल 1950 में रामानंद सागर ने सागर आर्ट कॉरपोरेशन प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की।

इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले 25 जनवरी 1987 को रामायण सीरियल की शुरूआत हुई, जोकि जुलाई 1988 तक चला। जहां उस समय दूरदर्शन पर इस शो को 45 मिनट तक के लिए टेलीकास्ट किया जाता था, तो वहीं अन्य सीरियल्स को 30 मिनट का स्लॉट मिलता था। जब रामानंद सागर की रामायण का टेलीकास्ट होता था, तो उस दौरान सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल बना जाता था। जिसकी आज के दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

मुंबई आने के बाद रामानंद सागर को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। शुरूआती दिनों में वह पृथ्वी थिएटर में पृथ्वीराज कपूर के साथ असिस्टेंट स्टेज मैनेजर के रूप में काम करते थे। वहीं कपूर के गाइडेंस में वह थिएटर के लिए कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया करते थे। करियर के शुरूआती दिनों में रामानंद सागर ने क्लैपर ब्वॉय के तौर पर साइलेंट फिल्म रेडर्स ऑफ द रोल में काम किया।

इसके अलावा उन्होंने राजकपूर की हिट फिल्म बरसात की कहानी भी लिखी थी। रामानंद सागर ने कई फिल्मों का डायरेक्शन किया था। उनकी निर्देशित फिल्म आंखें में अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री माला सिन्हा थीं। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी। इस फिल्म के लिए रामानंद सागर को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।

एक्सीडेंटल राजनेता, क्रांतिकारी अर्थशास्त्री

उमेश चतुर्वेदी

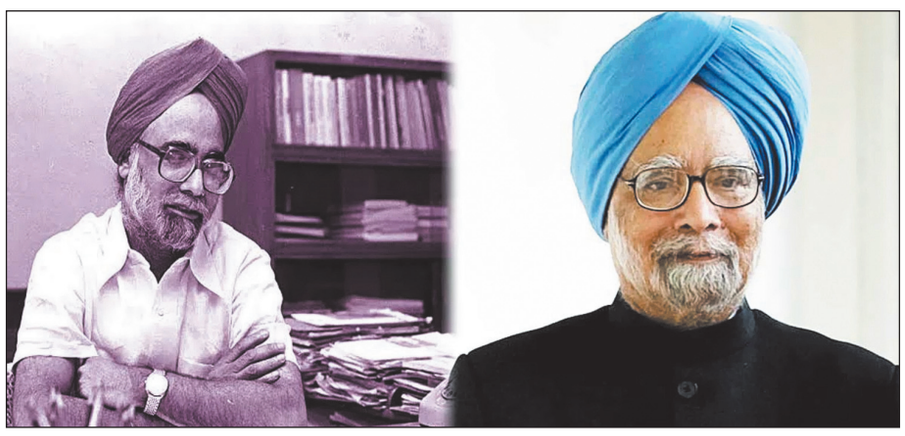

साल 1999 के आम चुनावों में दिल्ली की सात में छह सीटों पर तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। दक्षिण दिल्ली की इकलौती ऐसी सीट रही, जहां बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा को जीत मिली थी। मल्होत्रा के सामने जिन्हें हार मिली थी, वे राजनेता मनमोहन सिंह थे। उन दिनों मैं दैनिक भास्कर के दिल्ली ब्यूरो में काम करता था। अखबारी रिपोर्टिंग की एक रवायत है। वह विजेताओं को ही खोजती है और उनकी ही बात करती है। लेकिन हमारे तत्कालीन ब्यूरो चीफ और दिग्गज पत्रकार शरद द्विवेदी ने मुझे सफदरजंग रोड भेज दिया, जहां मनमोहन सिंह बतौर राज्यसभा सांसद रह रहे थे। शरद द्विवेदी का तर्क था कि मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले राजनेता हैं। उनके घर का माहौल देखना चाहिए और उस पर स्टोरी लिखनी चाहिए।

मैं जब मनमोहन सिंह के घर पहुंचा तो वहां करीब साठ-सत्तर कार्यकर्ता मौजूद थे। बंगले में एक तरह से उदासी छायी थी। एक ड्रम में रसना घोल रखी गई थी और आने वाले लोगों को पिलाई जा रही थी। वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, सिवा राजस्थान के रामनिवास मिर्धा के। मिर्धा भी चुपचाप एक कोने में खड़े थे। और तो और, वहां पत्रकार भी नहीं थे। मेरे पहुंचने के बाद बंगले में सिर्फ एक और पत्रकार आए। इस बीच साधारण से सफेद कुर्ता-पाजामा और नीली पगड़ी में मनमोहन सिंह मेरी तरफ मुखातिब हुए। उन्हें मैंने बतौर पत्रकार परिचय दिया तो उन्होंने कांपते हाथों से हाथ मिलाया और फिर उसी तरह तकरीबन कांपते हुए रसना का गिलास मुझे थमा दिया। उस वक्त मैंने बचकाना सा सवाल पूछ लिया था, क्या सोच रहे हैं? 'वैसा ही सोच रहे हैं, जैसा कोई हारा हुआ प्रत्याशी सोचता है।' उनका जवाब था।

मनमोहन सिंह को उसके बाद राज्यसभा और दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खूब देखा। वे कभी पढ़ते हुए दिखते तो कभी चुपचाप बैठे हुए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के इंडिया शाइनिंग अभियान को धत्ता बताते हुए कांग्रेस की अगुआई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने केंद्रीय सत्ता का दावेदार बन गया। तब शायद ही किसी ने सोचा था कि मनमोहन सिंह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त माना यह जा रहा था कि अगर किसी वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी तो प्रणब मुखर्जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी की बजाय मनमोहन सिंह पर भरोसा किया।

1991 में जब नरसिंह राव ने केंद्र की सत्ता संभाली, तब देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे विदेशी विनिमय के लिए अपना 67 टन सोना ब्रिटेन में गिरवी रखकर उसके एवज में 2.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा था। ऐसे माहौल में नई सरकार के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती थी। लेकिन नरसिंह राव ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण के साथ ही आर्थिक सुधारों की शुरूआत की। 1991 के चुनावों के बाद बनी नई सरकार ने 25 जुलाई 1991 को नया बजट पेश किया। उसी बजट को पेश करते हुए बतौर वित्त मंत्री देश को नई आर्थिक राह पर लेकर चल पड़े। उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार के साथ देश आर्थिक मोर्चों को फतह करते हुए आगे बढ़ चला। इस राह पर देश आज कितना आगे बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश का आज आर्थिक नक्शा बदला हुआ नजर आता है तो उसकी बड़ी वजह मनमोहन सिंह की रखी हुई बुनियाद ही है।

मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप ही याद किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को राजनेता भी होना चाहिए। मनमोहन आधुनिक और प्रचलित अर्थों में राजनेता नहीं थे। उनके ही मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने उन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा है। मनमोहन सिंह पर आरोप लगा कि वे कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। उनकी सरकार को सलाह देने के लिए सोनिया गांधी की अगुआई में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सलाहकार कम, आदेश देने वाली संस्था है। उनकी ही सरकार ने तीन साल की सजा पाने वाले राजनेताओं की संसद और विधानमंडल की सदस्यता खत्म होने को रोकने वाला अध्यादेश पारित किया था, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ कर एक तरह से उस अध्यादेश को प्रभावहीन कर दिया था।

मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, दस साल देश के प्रधानमंत्री रहे। पहले कार्यकाल में तो नहीं, लेकिन 2009 से 2014 के कार्यकाल में उनकी सरकार और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे। बेशक प्रधानमंत्री के रूप में उनके चरित्र और दामन पर कोई दाग नहीं लगा। लेकिन उनकी चुप्पी देश को खलती रही। इसलिए उन्हें मौनमोहन तक कहा जाने लगा था।

बिल्कुल मामूली परिवार में जन्मे मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र की ऊंची शिक्षा हासिल की। कैंब्रिज में अर्थशास्त्र की ऊंची शिक्षा ली, दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में अर्थशास्त्री रहे, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग में रहे, वित्त मंत्री रहते हुए इतिहास ही रचा।

मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री कुछ बयान विवादास्पद भी रहे। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उनका एक और बयान था कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक समारोह में उन्होंने जब कृतज्ञ भाव से अंग्रेजों की ओर से भारत को बड़ी देन अंग्रेजी को बताया था, तब भी उन पर सवाल उठे थे।

मनमोहन सिंह सरलता और सादगी की मिसाल थे। यह सादगी उनकी ताजिंदगी पहचान रही। वे सहज भी रहे। प्रणब मुखर्जी उनके राजनीतिक बॉस रह चुके थे। बाद के दिनों में उनके मंत्रिमंडल में मुखर्जी बतौर वित्त मंत्री शामिल थे। तब भी मनमोहन उन्हें पहले की तरह सर ही कहा करते थे। जिस पर मुखर्जी ने प्रतिवाद किया था और उन्हें सर कहने से रोक दिया था। इसका खुलासा खुद प्रणब मुखर्जी ने अपने एक साक्षात्कार में किया था।

हर व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं। मनमोहन भी इस मानवीय व्यवहार के अपवाद नहीं थे। अब वे हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनकी सादगी और सरलता तो याद रहेगी, देश के आर्थिक भाग्य को बदलने वाले के रूप में उनकी छाप सदा अमिट रहेगी। भारत इसके लिए उनका शुक्रगुजार ही नहीं, ऋणी भी रहेगा।

आज का इतिहास

1845 टेक्सास अमेरिका का 28वां राज्य बना।
1858 उत्तरी रेलवे कंपनी मैड्रिड, स्पेन में स्थापित की गई।
1860 फ्रांसीसी नौसेना के ला ग्लॉयर का मुकाबला करने के लिए, दुनिया का पहला पिरोनक्लाड युद्धपोत, ब्रिटिश रॉयल नेवी ने दुनिया का पहला पिरोया हुआ बख्तरबंद युद्धपोत, एचएमएस वारियर लॉन्च किया।
1890 संयुक्त राज्य की सेना ने घायल घुटने के नरसंहार में ग्रेटसाइक्स राष्ट्र के 150 से अधिक सदस्यों को मार डाला।
1891 शारीरिक शिक्षा शिक्षक जेम्स नाइस्मिथ ने मैसाचुसेट्स के इनफ्रिंगफील्ड में तेरह नियमों और प्रत्येक खिलाड़ी पर नौ खिलाड़ियों के साथ एक गेम पेश किया, जिसे उन्होंने बास्केट बॉल कहा।
1911 सुन यात सेन को नए चीन गणतंत्र का राष्ट्रपति घोषित किया गया। चीन में आम जनता और साम्यवादी कार्यकर्ता उन्हें चीन गणतंत्र का राष्ट्रपिता मानते हैं।
1911 सन यात-सेन को चीन के गणराज्य के अनंतिम राष्ट्रपति के रूप में नानजिंग में चुना गया था।
1937 आयरलैंड का संविधान, जिसे आज आयरलैंड गणराज्य के रूप में जाना जाता है, थेस्टेट का संस्थापक कानूनी दस्तावेज लागू हुआ।
1949 यूरोपीय देश हंगरी में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
1972 अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य के एवरग्लैड्स के समीप इस्टर्न त्रिस्टार जम्बो जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 101 लोगों की मौत हुई।
1972 जबकि पूर्वी एयर लाइंस फ्लाइट 401 के चालक दल एक इंस्ट्रूमेंटेशन समस्या को हल करने में व्यस्त थे, विमान 101 लोगों की मौत हो गई, फ्लोरेला एवरग्लेड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
1975 ब्रिटेन में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार का कानून लागू हुआ।
1977 विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थियेटर ड्राइव बंबई (अब मुम्बई) में खुला।
1988 ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरियाई पोस्ट ऑफिस संग्रहालय बंद हुआ।
1992 ब्राजील के राष्ट्रपति फर्नांडो कोलोर डी मेलो ने महाभियोग की कार्यवाही को जारी रखने से रोकने के लिए इस्तीफा दे दिया, लेकिन ब्राजील के सीनेट ने वैसे भी उन्हें दोषी पाया।
1997 एच 5 एन 1 फ्लू वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, हांगकांग सरकार ने 1.3 मिलियन मुर्गियों का वध किया।
2008 प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का निधन हुआ।

इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकालना संभव नहीं

संतोष पाठक

दिल्ली में लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रही आम आदमी पार्टी ने अब विपक्षी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को ही बाहर निकालने की मांग कर दी है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी की इस बेतुकी मांग पर अभी इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी दलों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन वास्तविकता तो सभी नेता जानते हैं। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकालने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन से बाहर भगाना संभव नहीं है। विडंबना देखिए कि, जिस विपक्षी इंडिया गठबंधन का गठन ही केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए किया गया है। उस गठबंधन में लोकसभा में 3 सीट की हैसियत रखने वाली आम आदमी पार्टी 99 लोकसभा सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर निकालने की बेतुकी मांग कर रही है।

ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि देश की वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति को समझने के बावजूद आम आदमी पार्टी इस तरह की बेतुकी मांग क्यों कर रही है ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव है। कहने को तो आप की सरकार दिल्ली और पंजाब यानी देश के दो राज्यों में है। ताकत और कामकाज के मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होने के कारण पंजाब में सरकार होने का अपना फायदा है लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल के ज्यादा मजबूत होने के बावजूद, यह राज्य केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की हार केजरीवाल की पार्टी के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा देगी। अगर आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई तो पार्टी में एक बड़ी टूट होने का भी खतरा पैदा हो सकता है और इसी डर ने आप के नेताओं को बुरी तरह से डरा दिया है।

ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में लगातार तीन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर, सरकार बनाने वाली आप को हार का डर क्यों सताने लगा है ? वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें और वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आप को इस बार हार का डर क्यों सताने लगा है ?

दरअसल, वर्ष 2013 में दिल्ली में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के तहत पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह झाड़ू का चयन किया था। उस समय यूपीए सरकार के अंदर से लगातार आ रहे घोटालों और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाते हुए केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगा दिया था। अपने पहले ही चुनाव में आप ने दिल्ली

की 70 में से 28 सीटों पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। 2013 के उस चुनाव में अंदरखाने आप की मदद कर, शीला दीक्षित को हराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले कुछ कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस नेताओं के मना करने के बावजूद आप को समर्थन देकर , केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। कांग्रेस के वोट बैंक पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। शीला दीक्षित ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूती से कांग्रेस के साथ जोड़ दिया था। झुग्गी-झोपडी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ मुसलमान भी मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। लेकिन धीरे-धीरे इन सभी मतदाताओं को आप ने अपने पाले में कर लिया। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और पानी देकर दिल्ली के झुग्गीवासियों और मिडिल क्लास को साध लिया। फ्री डीटीसी सफर की सुविधा देकर महिला मतदाताओं को लुभा लिया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में रहने वाले बिहार और यूपी के लोगों को भी तवज्जों देकर एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर लिया। भाजपा को हराने के नाम पर मुस्लिम मतदाता भी केजरीवाल के साथ जुड़ गए।

कांग्रेस उलझन और ऊहापोह की स्थिति के कारण अपने इसी वोट बैंक को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से छीन नहीं पा रही थी क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे आप को दोस्त माने या दुश्मन। दिल्ली में लड़ रहे कांग्रेसी नेताओं का भी अपने ऊपर से भरोसा ही उठ गया था कि वे केजरीवाल से लड़ भी सकते हैं और यही बात आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा वरदान था।

लेकिन इस बार जिस अंदाज में अजय माकन ने सीधे-सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला,युवा कांग्रेस ने संसद मार्ग थाने जाकर उनके खिलाफ शिकायत दी और कांग्रेस ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार दिया, उससे आप के मुखिया बुरी तरह से डर गए हैं। आप को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में पूरी ताकत से विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो आप के लिए चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं नामुकिन हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि नई दिल्ली के मतदाताओं को यह लगने लगा है कि उन्होंने शीला दीक्षित को 2013 में विधानसभा चुनाव में हराकर गलती की थी और अब वह उनके बेटे संदीप दीक्षित को जीताकर अपनी 2013 की गलती का प्रायश्चित 2025 में करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद की विधानसभा सीट हार जाते हैं तो उनके लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी, अजय माकन, कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस उम्मीदवारों के दिलों-दिमाग पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए यह बेतुकी मांग करनी शुरू कर दी है। यहीं पर राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह देखना होगा कि दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत बनाने के मिशन में जुटे नेताओं का राहुल गांधी खुल कर और पूरी मजबूती के साथ, साथ दे पाते हैं या नहीं ?

किन्हें भूलें और किन्हें याद रखें

पूरन चंद सरीन

प्रत्येक वर्ष बहुत कुछ छोड़कर जाता है जो आने वाले वर्ष के लिए महत्वपूर्ण तो होता ही है साथ में चेतावनी भी कि यदि जो भूलें हुई हैं वह दोहराई गईं तो कीमत चुकानी होगी और जो श्रेष्ठ तथा जनहित के काम हुए, वे आगे जारी न रहे तो दुष्परिणाम भुगतने होंगे। यह व्यक्ति, समाज, देश यानी सरकार सब पर समान रूप से लागू होता है। इस वर्ष का आरंभ भव्य राम मंदिर से हुआ और अंत इस बहस से हो रहा है कि राम आज कितने प्रासंगिक हैं। संविधान और उसके निर्माताओं को लेकर वाद विवाद ही नहीं, संसद में मारपीट और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। जनमानस लक्ष्मण के कार्टून की तरह बस ताक रहा है कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर को ही सन 1885 में इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए तब बंबई में अधिवेशन हुआ था और गुलाम भारत को एक नई ज्योति दिखाई दी थी कि वह स्वतंत्रता की उम्मीद रख सकता है। यह राष्ट्रीय दल आज किस अवस्था में है, यह सभी जानते हैं और इस बारे में थोड़ा कहा भी काफी समझा देता है। इस वर्ष देश में जैसे चुनावों की बहार ही छाई रही। लोकसभा और अनेक राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। 2014 में एक विकल्प के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। शेष सभी दल 'हम भी दौड़ में हैं' की तर्ज पर जहां तहां जुगनूं की तरह चमक दिखाते रहते हैं। वे कसमसाते रहते हैं कि कैसे इस मदमस्त हाथी की सधी चाल को रोका जाए। स्थिति यह है कि गजराज भूल रहे हैं कि एक चींटी उन्हें धूल चटा सकती है। सत्ता का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं लेकिन जब यह सिर चढ़कर बोलने लगे तब पतन होना निश्चित है। सत्ताधारी चेत जाएं तो ठीक वरना नियति किसी को बख्शती नहीं। एक देश एक चुनाव की मीमांसा के लिए संसदीय समिति बना दी अन्यथा अधिकतर बिल तो बिना चर्चा के पास कर लिए जाने की परंपरा बन रही थी। विपक्ष पूरा जोर लगाता रहा कि संसद की कार्रवाई चलने ही न दी जाए। भारत के इतिहास में शामिल इन पन्नों से अगली पीढ़ी क्या सीखेगी, यह सोचना है! अटल बिहारी वाजपेयी की इस वर्ष सौंवीं जयंती थी। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी कथनी विज्ञानी सोच पर आधारित थी और करनी ऐसी कि विश्व में अमरीका जैसे सूरमा दांत किटकिटाने के अतिरिक्त कुछ न कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ में उदाहरण बना भाषण हो, केवल एक वोट की कमी से सरकार का त्याग कर देना हो या दुनिया भर की सैटेलाइट क्षमता को चकमा देकर आणविक परमाणु हथियार से देश को सशक्त करना हो, हमेशा याद रहेंगे। उनके संपर्क में आने, उनसे बातचीत करने और उनका मुक्त अट्टहास सुनने का अवसर जिन्हें मिला, वे धन्य हैं। अटल जैसा न भूतो न भविष्यति। भारत की नदियों को जोड़ कर उनके जल का इस्तेमाल सिंचाई, अतिवृष्टि और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरा भरा बनाने की कल्पना का जन्म अटल जी के ही मन में हो सकता था। उनके स्वप्न को धराशायी करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जो नरसिम्हा राव की खोज थे और जिन्हें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय जाता है, वे अपने कार्यकाल में ज्यादा कुछ न कर सके। वे भी अब 92 वर्ष की आयु में दिवंगत हो चुके हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। यह वर्ष सिने संसार के शोमैन और निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राज कपूर की सौंवीं वर्षगांठ मनाने के साथ समाप्त हो रहा है। वे अकेले ऐसे कलाकार थे जो उस जमाने में रूस जैसे शक्तिशाली देश में अपनी कला का लोहा मनवा चुके थे। दो देश कैसे एक-दूसरे के साथ आत्मीय संबंध बना सकते हैं, इसका उदाहरण राज कपूर के अतिरिक्त किसी और का नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा को नई पहचान देने के प्रयास में सफल और फिल्मों के माध्यम से साधारण व्यक्ति की व्यथा को समझने में उसका उपयोग करने में कुशल श्याम बेनेगल का भी निधन हुआ। वे 91 वर्ष के हुए थे और कुछ ही दिन पूर्व अपनी वर्षगांठ मनाई थी। बहुत सरल, कम बोलने वाले और थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहने में माहिर थे। इस वर्ष उद्योगपतियों में प्रमुख रतन टाटा भी नहीं रहे, वे भारत रत्न आधिकारिक सम्मान को गौरव प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें जल्दी मिलेगा, यह कामना है। उनकी बनाई कंपनियों ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। नए उद्यमी उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं और उनकी दूरदृष्टि और प्रबंधन योग्यता का वरण करना चाहते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि प्रत्येक भारतीय आधुनिक टैक्नोलॉजी अपनाने और बदलते परिवेश में स्वयं को ढाल पाएगा। गाड़ी स्टेशन से छूट गई तो उसमें सवार होने की नौबत कब आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता।

सियासी पिच पर चौंकाने वाला रहा साल 2024

नितिन गौतम

साल 2024 सियासी तौर पर बेहद चौंकाने वाला रहा और इस साल के चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया कि देश की जनता को साधना इतना भी आसान नहीं है। जनता ने लोकसभा चुनाव से लेकर विभिन्न विधानसभा चुनाव तक ऐसा जनादेश दिया, जिसका अंदाजा राजनीति के बड़े-बड़े विश्लेषक भी नहीं लगा पाए। तो आइए जानते हैं कि 2024 को सियासी पिच पर चौंकाने वाले साल के रूप में क्यों याद किया जाएगा।

लोकसभा के नतीजों ने एनडीए को दिया झटका

इस साल 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव से पहले देश में भाजपा की हवा होने का दावा किया जा रहा था और खुद भाजपा भी आत्मविश्वास से लबरेज थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने चुनाव से पहले नारा दिया कि %इस बार 400 पार%। विभिन्न राजनीतिक पंडितों ने भी माना कि भाजपा रिकॉर्ड सीटें जीत सकती है और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का आंकड़ा 400 पार जा सकता है। हालांकि जब नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। भाजपा बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और महज 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि तेदेपा और जदयू और अन्य सहयोगी दलों की मदद से भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने में सफल रही।

संविधान को लेकर नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रहा विपक्ष

आम चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आने का दावा किया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है और वे अभी भी देश के सर्वमान्य नेता हैं। आम चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन ने आरोप लगाया कि भाजपा को बंपर बहुमत मिला तो वे संविधान बदल देंगे। विपक्ष चुनाव प्रचार में संविधान को लेकर ऐसा नैरेटिव गढ़ने में सफल रहा और यही वजह रही कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे क्रांतिकारी फैसलों के बाद भी भाजपा अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। देश की हिंदी बेल्ट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि हिंदी बेल्ट

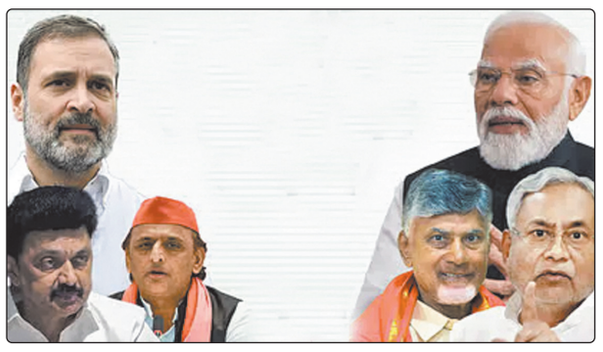

के ही सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा महज 33 सीटें जीत सकी, जबकि 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने यूपी की 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

गठबंधन की राजनीति की वापसी

देश में गठबंधन राजनीति का लंबा इतिहास रहा, लेकिन 2014 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि देश से गठबंधन राजनीति की विदाई हो चुकी है और लोग अब किसी भी पार्टी को निर्णायक जनादेश देना पसंद करते हैं। 2024 के चुनाव में भी यही उम्मीद थी कि जनता स्पष्ट बहुमत देगी, लेकिन चुनाव नतीजों ने सारी उम्मीदों को ध्वस्त करते हुए गठबंधन राजनीति को फिर से जिंदा कर दिया। पिछले दो कार्यकाल में बंपर जनादेश पाने वाली भाजपा इस बार गठबंधन के साथियों पर निर्भर है। वहीं विपक्ष भी गठजोड़ बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।

ओडिशा में नवीन पटनायक का 20 साल का शासन हुआ समाप्त

लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए। ओडिशा चुनाव के नतीजे भी खास रहे और राज्य में बीते 24 वर्षों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पार्टी ने राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 78 पर जीत दर्ज की। वहीं नवीन पटनायक की बीजद 51 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। आंध्र प्रदेश में भी तेदेपा की जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे आए तो सब हैरान रह गए क्योंकि चुनाव में वाईएसआरसीपी का लगभग सूपड़ा साफ हो गया।

हरियाणा ने कांग्रेस को रुलाया

इस साल हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हुए जिनके नतीजों ने सभी राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया। पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज भाजपा के इस बार सत्ता विरोधी लहर और किसानों के विरोध के चलते हारने की भविष्यवाणी की जा रही थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने सभी को चौंकाते हुए भाजपा को विजेता बना दिया। नायब सिंह सैनी राज्य के मुख्यमंत्री बने।

महाराष्ट्र में चला एक हैं तो सेफ हैं का जादू

हालिया नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों ने पूरे साल चुनाव नतीजों के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए ये साबित कर दिया कि हमारे देश का लोकतंत्र काफी मजबूत है और इसे लेकर पूर्वानुमान लगाना इतना भी आसान नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। वहीं जनता की सहानुभूति की उम्मीद लगाए बैठीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की शिवसेना को बुरी हार का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन से उत्साहित इन पार्टियों के नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर दिया था, लेकिन चुनाव नतीजों ने पूरी बाजी ही पलट दी। कांग्रेस की हालत भी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी खराब रही। देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए सीएम बने हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद भाजपा को बहुमत की उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी न हो सकी। वहीं झारखंड में भी भाजपा को झटका लगा और हेमंत सोरेन की सरकार की सत्ता में वापसी हुई। उपचुनाव में भी कई सीटों पर हैरान करने वाले नतीजे देखने को मिले। खासकर यूपी में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने वाली सपा को हाल ही में सात सीटों पर हुए उपचुनाव में महज दो सीटों से ही संतोष करना पड़ा।

मुफ्त की चुनावी घोषणाएं बिगाड़ रहीं हैं आर्थिक सेहत

योगेंद्र योगी

दिल्ली चुनाव को अभी एक महीने से ज्यादा का समय बाकी है। उससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये आएंगे। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद इसको बदलकर 2100 रुपए करेंगे। चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली आप अकेली पार्टी नहीं हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों में खैरात बांटने की होड़ लग जाती है। इसका एकमात्र मकसद चुनाव जीतना है। इसके नुकसान-फायदों की राजनीतिक दलों का परवाह नहीं हैं। यह अलग बात है कि चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना तो खरबूजे को ही है। मसलन फ्री का माल लेने वाले को भी आखिरकार इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी न किसी रूप में टैक्स का बोझ उन पर भी पड़ता है। फ्री की योजनाओं का फायदा उठाने वाले भी इससे बढने वाली महंगाई की मार से बच नहीं सकते।

इससे पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और तीन साल के लिए फ्री इंटरनेट का वायदा किया था। गहलोत ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत सवा करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये जमा कराए। कांग्रेस ने वादा किया था कि उसकी सरकार आई तो हजार नहीं बल्कि 1,500 रुपये दिए जाएंगे। शिवराज ने

युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9000 टॉपर्स को एक-एक स्कूटी देने का भी ऐलान किया था। चुनावी रेवड़ी बांटना का कल्चर शुरु से ही विवादों से घिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक विशेषज्ञ, चुनाव आयोग और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक इस पर चिंता जता चुके हैं। कोई भी राजनीतिक दल व्यापक देशहित से जुड़े ऐसे मुद्दों का समाधान तलाशना तो दूर बल्कि चर्चा तक करना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन और अन्य मुफ्त योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर लोगों को फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन देना समय की जरूरत थी, लेकिन अब रोजगार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, तो मतलब सिर्फ टैक्सपेयर्स ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है। यह स्थिति गंभीर विचार का विषय है। वर्ष 2022 में श्रीलंका का आर्थिक संकट सामने आया तो इसने दुनियाभर की सरकारों को चेता दिया। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि श्रीलंका से सबक लेते हुए हमें मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं हो सकती, लेकिन वहां से आने वाला सबक बहुत मजबूत है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। मोदी ने कहा था कि हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।

भारत में ऐसी लुभावनी पर आर्थिक तौर पर घातक चुनावी वायदों की शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। वर्ष 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा किया। डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि, डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी अन्नाद्रमुक ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कम्प्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा कर दिया। शादी होने पर महिलाओं को 50 हजार रुपये और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल देने का वादा भी किया।

नतीजे आए तो अन्नाद्रमुक की सरकार बन गई। 2006 के चुनावी वादे पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफी हद तक हिला देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह-मशविरा कर एक आचार संहिता बनाए। इसके बाद 2015 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी भी की, लेकिन उसके बावजूद चुनावों में फ्रीबीज का ऐलान होता ही रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कहा था, ऐसी योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स भागीदारी कम हो तो वो फ्रीबीज होती हैं। वर्ष 2022 पिछले साल आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। स्टेट फाइनेंसेस- अ रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन पांच राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल थे। चुनावी वादों के कारण बढ़ रही मुद्रास्फीती और महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। राजनीतिक दलों का इससे सरोकार नहीं है। सत्ता में आने के बाद सरकारें फ्री देने के वादे पूरा करने के लिए टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही हैं। होना तो यह चाहिए कि कोई राजनीतिक दल जब ऐसी मुफ्त की चुनावी घोषणाओं का ऐलान करे तो साथ ही यह भी बताए कि इसके लिए धन का इंतजाम कैसे किया जाएगा। मसलन इसके एवज में करदाताओं पर कितना बोझ पड़ेगा। जब तक हिसाब-किताब पारदर्शी नहीं होगा तब तक ऐसी योजनाओं देश पर बोझ साबित होती रहेंगी।

मनमोहन सिंह : बेजोड़ ईमानदारी और दूरदर्शिता वाले राजनेता

भूपेंद्र सिंह हुड्डा

आज, भारत अपने सबसे प्रिय नेताओं में से एक डा. मनमोहन सिंह के निधन से शोक में है। 26 दिसंबर, 2024 को उनका निधन, एक ऐसे युग का अंत है जिसको उनकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने परिभाषित किया था। उनका संघर्ष पूर्ण जीवन व भारत के राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान भारत के इतिहास का हिस्सा रहेगा। डा. सिंह का जीवन एक साधारण परिवेश से शुरू हुआ, पर भारत व पूरे विश्व के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक बनने की उनकी यात्रा सभी के लिए प्रेरणादायक है। एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री के रूप में डा. सिंह ने अपना नाम भारतीय इतिहास में अंकित कर लिया। उस समय देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। उस समय उन्होंने साहसिक आर्थिक सुधारों की शुरूआत की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और इसे दुनिया के लिए खोल दिया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में डा. सिंह का कार्यकाल भारत के आधुनिक इतिहास में एक निर्णायक काल था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को सशक्त बनाया, खासकर हाशिए के समुदायों के लोगों को। ये केवल नीतियां नहीं थीं, बल्कि वंचित वर्गों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और एक समतापूर्ण समाज के उनके विचार की अभिव्यक्तियां थीं। अपने राष्ट्रीय योगदान के अलावा, डा. सिंह हमेशा हरियाणा के विकास के लिए असाधारण प्रतिबद्ध थे, जो उनके दिल के करीब था। यमुनानगर में उनके कोहली परिवार की जड़ों ने उन्हें इस क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से जोड़ा और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, हरियाणा ने उल्लेखनीय विकास और परिवर्तन देखा। यह उनके नेतृत्व में ही था कि हरियाणा भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान झज्जर जैसे प्रमुख संस्थानों का घर बन गया। औद्योगिक आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए उनके समर्थन ने औद्योगिक मॉडल टाऊनशिप की स्थापना की, जिससे राज्य में विनिर्माण और रोजगार का केंद्र बना, जिससे हरियाणा रोजगार और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में नंबर एक बन गया। उन्होंने राज्य में मैट्रो रेल विस्तार का भी समर्थन किया, जिससे हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब आ गया, और कनैक्टिविटी बढने के साथ, राज्य में आर्थिक अवसर बढ़े। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी डा. सिंह का हरियाणा के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। वे अक्सर मुझसे इन परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लेते थे, जो राज्य और उसके लोगों के कल्याण के लिए उनकी चिंता का प्रमाण है। डा. सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे उनसे कई बार बातचीत करने का सौभाग्य मिला। उनके नेतृत्व की विशेषता खुलेपन, संवाद और आम सहमति बनाने की इच्छा थी। मुझे याद है कि जब मैं सांसद था, तो वित्तमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान खाद व उर्वरक मूल्यों में हुई वृद्धि को वापस लेने पर चर्चा करने के लिए किसानों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा था। डा. सिंह का स्पष्ट जवाब था कि हमारे किसानों का कल्याण हमारी नीतियों के केंद्र में रहना चाहिए।

महान अर्थशास्त्री असरदार सरदार

डॉ मनमोहन सिंह

देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सहित पूरे देश सहित पूरी दुनिया के उनके शुभचिंतकों ने शोक व्यक्त किया हैद्य डॉ मनमोहन सिंह का जाना भारतीय राजनीति में एक बड़ा नुकसान हैद्य डॉ साहब जब आप पीएम थे तब मुल्क आपके साथ न्याय नहीं कर सका, आपको वो इज्ज़त नहीं दे सका जिसके आप हकदार थेद्य 2014 में एक इंटरव्यू में आपने कहा था, मेरा पूरा विश्वास है कि मौजूदा मीडिया और संसद में मौजूद विपक्षी पार्टियों की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा दयालु होगा मुझे लगता है इतिहास आपके साथ न्याय करेगाद्य अलविदा डॉ साहब ये मुल्क आपको डिजर्व नहीं करता थाद्य डॉ मनमोहन सिंह दो बार प्रधानमंत्री ज़रूर बने लेकिन वे कभी भी खुद को राजनेता नहीं मानते थे, पार्टी के आदेश पर जीवन में सिर्फ़ एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गएद्य मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका राजनीतिक जनाधार नहीं हैद्य उन्होंने कहा था, राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है, और मैं चुनाव नहीं जीत सकता इसलिए मैं खुद को नेता नहीं मानताद्य फ़िर उन्होंने चुनाव से तौबा कर लीद्य

डॉ मनमोहन सिंह ने एक दशक अधिक समय तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी और विकास का नेतृत्व किया। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर देखी, जो औसतन 7.7ब्र रही और लगभग दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनी, 1971 में डॉ. मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव; योजना आयोग के उपाध्यक्ष; भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष; प्रधानमंत्री के सलाहकार; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर थे। उनके कार्यकाल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित व्यापक कानूनी सुधार किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया और शहरी बैंक विभाग की स्थापना की गई। आरबीआई में अपने कार्यकाल के बाद, उन्होंने वित्त मंत्री नियुक्त होने से पहले कई पदों पर काम किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय था कि उन्होंने भारत में उदारीकरण और व्यापक सुधारों की शुरुआत की।

डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों को उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जानकार कहते हैं कि डॉ मनमोहन सिंह अगर 1991 में वित्तमंत्री नहीं बने होते तो शायद भारत कभी भी आर्थिक आपातकाल से बाहर नहीं आताद्य बतौर वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक दर को जो आयाम दिया जिसके कारण आज भी भारत को फायदा होता हैद्य वित्तमंत्री, प्रधानमंत्री आएंगे, जाएंगे लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्र का जानकार उनके जैसा विद्वान शायद ही इस मुल्क को मिले इसलिए ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र का आर्किटेक्ट कहा जाता हैद्य डॉ मनमोहन सिंह जी को अब तक के भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बेहतर वित्तमंत्री के रूप में याद रखा जाएगाद्य वहीँ प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगाद्य आरटीआई, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी बिल, परमाणु समझौता जैसे महान सुधारों के लिए याद किया जाएगाद्य

दुनिया के सबसे बड़े मुल्क अमेरिका के प्रभावशाली राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती हैद्य हालांकि बहुत कम बोलते हैं लेकिन जितना भी बोलते हैं, कमाल बोलते हैंद्य पूरी दुनिया उनकी अर्थशास्त्र की जानकारी और उनके ज्ञान से प्रभावित रही है कैंब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जैसे बड़े-बड़े विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्याख्यान भविष्य में विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगेद्य ये मुकाम डॉक्टर मनमोहन सिंह की विद्वता को दर्शाता है, शायद इस मुल्कों को दोबारा ऐसा विद्वान प्रधानमंत्री मिलेद्य

देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार

वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड और वित्तमंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार; कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार.. उनको जापानी निहोन किजई शिम्बुन एवं अन्य संघो की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. मनमोहन सिंह को कैंब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड और अन्य कई विश्वविद्यालयों की तरफ से मानद उपाधियां प्रदान की गई हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में और वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) के सदस्य रहे जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। वहीं डॉ. मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप के शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा, जिनसे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा।

क्यों हमेशा नीली पगड़ी पहनते थे मनमोहन सिंह, जानिए पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी ये रोचक बात

26 दिसंबर, गुरुवार रात 9:51 बजे, भारत ने अपने महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को खो दिया। वे 92 वर्ष के थे और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। वे अपनी सादगी और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके पहनावे का एक विशेष हिस्सा, नीली पगड़ी, हमेशा चर्चा का विषय रहा है। आखिर क्यों मनमोहन सिंह हमेशा नीली पगड़ी पहनते थे? इसका जवाब उन्होंने 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और नीली पगड़ी का कनेक्शन

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉ. मनमोहन सिंह को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, प्रिंस फिलिप द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस अवसर पर प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में मजाकिया अंदाज में कहा,

'आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं।'

इस टिप्पणी का जवाब देते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने खुलासा किया कि हल्का नीला रंग उनके अल्मा मेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रतीक है। उन्होंने कहा,

'कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की यादें बहुत गहरी हैं। हल्का नीला रंग मेरा पसंदीदा है, इसलिए यह अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है।'

हल्का नीला रंग: डॉ. मनमोहन सिंह की पहचान

नीली पगड़ी डॉ. मनमोहन सिंह की पहचान बन चुकी थी। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत पसंद को दर्शाता था, बल्कि उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक भी था। हल्का नीला रंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पारंपरिक पहचान से जुड़ा हुआ है।

मोदी ने दी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि,

कहा- सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा

उन्हें एक दयालु इंसान, विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया और कहा कि उन्हें एक दयालु इंसान, विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि उनका जीवन भविष्य की पीढ़ियों को सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है।

डॉ. सिंह का निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति

मोदी ने कहा कि डॉ. सिंह का निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। विभाजन के दौरान भारत आने के बाद बहुत कुछ खोने के बावजूद उन्होंने इन उपलब्धियों को हासिल किया।

उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह का जीवन भविष्य की पीढ़ियों को सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाए। मोदी ने जोर देकर कहा कि डॉ. सिंह को हमेशा एक दयालु व्यक्ति, एक विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा।

एक अर्थशास्त्री के रूप में विभिन्न स्तरों पर भारत सरकार में डॉ. सिंह के कई योगदानों को मोदी ने रेखांकित किया और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनकी भूमिका की सराहना की।

सिंह ने देश को वित्तीय संकट से बाहर निकाला

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारतरत्न पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में वित्तमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को वित्तीय संकट से बाहर निकाला और एक नए आर्थिक पथ पर अग्रसर किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के विकास और प्रगति में डॉ. सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों और देश के विकास के प्रति डॉ. सिंह की प्रतिबद्धता को हमेशा उच्च सम्मान दिया जाता है।

सिंह का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिम्ब रहा

मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि डॉ. सिंह का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिम्ब रहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉ. सिंह का विशिष्ट संसदीय जीवन उनकी विनम्रता, सौम्यता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है।

प्रधानमंत्री ने याद किया कि इस वर्ष के आरंभ में राज्यसभा में सिंह का कार्यकाल पूरा होने पर भी उन्होंने डॉ. सिंह के समर्पण को सभी के लिए

प्रेरणा बताते हुए उनकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद डॉ. सिंह ने व्हीलचेयर पर बैठकर महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लिया और अपने संसदीय कर्तव्यों को पूरा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने और शीर्ष सरकारी पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉ. सिंह अपनी साधारण पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले।

उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहे, सभी दलों के व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखा और सभी के लिए आसानी से सुलभ रहे। मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और बाद में दिल्ली में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर डॉ. सिंह के साथ अपनी खुली बातचीत को भी याद किया।

उन्होंने डॉ. सिंह के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी नागरिकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिंह को उनके 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि डॉ. मनमोहन सिंहजी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के लिए उनके योगदान को भारत हमेशा याद रखेगा।

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दोपहर में 12.30 बजे स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित करने वाले थे। यह एक विशाल राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों और मंत्रियों को भाग लेना था। लेकिन मनमोहन सिंह के सम्मान में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।

पूर्व वित्तमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया था। वे 92 साल के थे। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। वे 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे।

पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे मनमोहन सिंह, ब्रिटेन के पीएम से क्यों कही थी यह बात

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है कि जुलाई 2011 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि यदि ऐसा कोई और हमला होता है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी।

मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 13 जुलाई 2011 को तीन बम विस्फोट हुए थे। ये धमाके ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादर पश्चिम क्षेत्रों में शाम 6:54 बजे से 7:06 बजे के बीच हुए थे जिसमें 26 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हो गए थे।

वर्ष 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'फॉर द रिकॉर्ड' में कैमरन ने लिखा, 'प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। वह एक संत पुरुष थे, लेकिन भारत के सामने आने वाले खतरों के बारे में वह बेहद सख्त थे। बाद में एक यात्रा पर उन्होंने मुझसे कहा कि जुलाई 2011 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले जैसा एक और आतंकवादी हमला अगर हुआ तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी।'

वर्ष 2013 में अमृतसर की यात्रा के दौरान जब वह और सिंह प्रधानमंत्री थे, तब कैमरन ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश इतिहास की एक बेहद शर्मनाक घटना बताया था।

पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये के अवमूल्यन, करों में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की अनुमति देकर एक नई शुरुआत की। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को मनरेगा और आरटीआई की सौगात दी थी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली में आज चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले एक सप्ताह में दिल्ली में दो सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि रविवार को मोदी रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे और रोहिणी के जापानी पार्क में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी को वह भाजपा सांसद मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र पूर्वोत्तर दिल्ली में नई दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग के उद्घाटन सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधिकारिक कार्यक्रम के बाद एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली बीजेपी सार्वजनिक बैठकों में भारी भीड़ उमड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य इकाई ने सभी मंडल अध्यक्षों से रोहिणी में बैठक के लिए लोगों की कम से कम दो बसें लाने को कहा है।

30 दिसंबर को संदेशखाली जाएंगी ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह 30 दिसंबर को संदेशखाली की यात्रा करेंगी, जो कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख से जुड़े भूमि कब्जाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के बाद उत्तरी 24 परगना में द्वीप की उनकी पहली यात्रा होगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर को संदेशखाली जाऊंगी। लोकसभा चुनाव से पहले कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं संदेशखाली कब आऊंगी। मैंने उनसे कहा था कि मैं वहां जाऊंगी। उत्तर 24 परगना जिले के 16 ग्राम पंचायत क्षेत्रों वाले संदेशखाली में इस साल 5 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हफ्तों तक तनाव देखा गया था। स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उन पर और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

फॉर्मूला-ई रेस मामले में केटीआर को ईडी का समन

हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव को तलब किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और पूर्व हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) . इसी मामले में मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को भी तलब किया गया है। केटीआर को 7 जनवरी को बुलाया गया है, जबकि कुमार और रेड्डी को क्रमशः 2 और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह जांच तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद की जा रही है। आरोप एचएमडीए से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ) को कुल 55 करोड़ रुपये के अनधिकृत वित्तीय हस्तांतरण पर केंद्रित हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि धनराशि अनिवार्य सरकारी मंजूरी के बिना हस्तांतरित की गई थी।

चिराग ने 2030 को लेकर जता दी अपनी बड़ी इच्छा

पटना। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वह आने वाले दिनों में बिहार पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए 2030 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। पासवान ने कहा कि वह बिहार की बेहतरी के लिए काम करने के उद्देश्य से राजनीति में आये हैं। एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह मेरी योजनाओं का हिस्सा था कि मैंने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पर जोर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद को 2030 में बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में देखना चाहता हूं। मैं खुद को राज्य की राजनीति से अधिक परिचित देखता हूं। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि पासवान ने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने से परहेज किया है क्योंकि एनडीए, जिसमें उनकी पार्टी एक भागीदार है, पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के सिलसिले में पंजाब को 31 दिसंबर तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। पंजाब ने डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित न कर पाने पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि यदि जरूरत हो तो डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाए। प्रमुख किसान नेता 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। न्यायमूर्ति कांत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि कृपया उन्हें बताएं कि जो लोग दल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।

कांग्रेस को क्यों याद दिलाया जा रहा नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार?

कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर केंद्र से किए सवाल

नईदिल्ली। सरकार ने कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के कांग्रेस के अनुरोध पर सहमत हो गई है। शनिवार को उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सरकार की यह घोषणा कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद आई कि सिंह के लिए दिल्ली में विश्राम स्थल के उसके अनुरोध को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने कहा सरकार को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष से पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और डॉ. मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। एक ट्रस्ट बनाना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी। कांग्रेस चाहती थी कि सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया जा सके। संयोग से, यह सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी जिसने अलग स्मारकों की मांग पर रोक लगाई थी। 2013 में यूपीए कैबिनेट ने जगह की कमी को देखते हुए राजघाट पर एक सामान्य स्मारक स्थल राष्ट्रीय स्मृति स्थल स्थापित करने का निर्णय लिया। कांग्रेस के आरोपों के बाद लोग नरसिम्हा राव की याद दिला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद करना चाहिए कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया था। फिर 10 साल की यूपीए सरकार के दौरान कोई स्मारक भी नहीं बनवाया गया।

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रखा रहा शव

दिसंबर 2004 में राव की मृत्यु हो गई। कांग्रेस तब तक केंद्र में सत्ता में वापस आ गई थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। राव की मृत्यु के एक दिन बाद, शव को नई दिल्ली के अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के द्वार पर लाया गया। लेकिन राव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी के गेट के बाहर फुटपाथ पर रखा गया था। इस बात की पुष्टि वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी आत्मकथा Courage & Commitment में की थी, जो 2016 में प्रकाशित हुई। तब कांग्रेस का बचाव करते हुए यह तर्क दिया गया था कि राव का शरीर इतना भारी था कि उसे गन कैरेज से उठाकर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर रखना मुश्किल था। परिजनों की इच्छा का हवाला देकर शव को हैदराबाद ले जाया गया। विडम्बना तो यह थी कि संजय गांधी जो कभी भी किसी भी राजपद पर नहीं रहे, की समाधि राजघाट परिसर में बनी। केवल पांच महीने रहे प्रधान मंत्री, जो लोकसभा में बैठे ही नहीं, (चरण सिंह) के लिये किसान घाट बन गया। सात माह कांग्रेस के सहारे प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह का भी एकता स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। मगर सम्पूर्ण पांच साल की अवधि तक प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का शव सोनिया गांधी ने सीधे हैदराबाद रवाना करा दिया था। दिल्ली में उनके नाम कोई स्मारक नहीं, कोई गली नहीं।

कांग्रेस और नरसिम्हा राव के रिश्तों में क्यों आई खटास

प्रधानमंत्री बनने के बाद वे सोनिया गांधी से नियमित अंतराल पर मिलते रहते थे लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी को कभी-भी सत्ता केंद्र के रूप में उभरने नहीं दिया। नटवर सिंह ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि नरसिम्हा राव को लगा कि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने ऐसा ही किया। यह बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई। नरसिम्हा राव के एक बयान %जैसे इंजन ट्रेन की बोगियों को खींचता है वैसे ही कांग्रेस के लिए यह जरूरी क्यों है कि वह गांधी-नेहरू परिवार के पीछे-पीछे ही चले? ने इस दूरी को और बढ़ा दिया। कांग्रेस के बाहर और भीतर एक बड़ा तबका है, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराये जाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जिम्मेदार मानता है। राहुल गांधी ने भी एक बार कहा था कि उस समय अगर मेरे परिवार से कोई प्रधानमंत्री होता तो मस्जिद नहीं गिरती। नरसिम्हा राव ने लोकसभा में कहा भी था कि रामभक्तों (भाजपा) से तो सामना किया जा सकता है, पर भगवान राम से नहीं।

महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को महिला सम्मान योजना के नाम पर पंजीकरण कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस कमिश्नर को यह आदेश कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर दिया गया। कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के प्रधान सचिव एलजी ने दिल्ली की प्रत्येक महिला (18 वर्ष से अधिक) को आम आदमी पार्टी द्वारा की गई घोषणा के संबंध में मुख्य सचिव, दिल्ली और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पत्र लिखा है।

1000 प्रति माह, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वापस निर्वाचित होने पर राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलजी की इच्छा है कि मुख्य सचिव गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच कराएं। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार के एक विभाग ने बुधवार को कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए एकत्र किया जा रहा डेटा धोखाधड़ी का मामला है, उन्होंने कहा कि वे महिलाओं से फोन नंबर और पते एकत्र कर रहे हैं। दीक्षित ने कहा कि हम कह रहे हैं कि अगर यह धोखाधड़ी का मामला है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए और उन दो लोगों- आतिशी और केजरीवाल- के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने यह धोखाधड़ी की है। सभी क्क कार्यकर्ताओं को (जानकारी एकत्र करने से) रोका जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।

उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश तो भड़के केजरीवाल

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) की कल्याणकारी योजनाओं की जांच के आदेश के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भाजपा और कांग्रेस पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम महिलाओं को 2100 रुपये और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज करेंगे। ये दोनों योजनाएं जनता के लिए इतनी फायदेमंद थीं कि इनके लिए लाखों लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था।

केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि इससे बीजेपी घबरा गई, कई बीजेपी नेताओं ने मुझसे कहा कि जीतने की बात तो छोड़िए, कई जगहों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। पहले अपने गुंडे भेजे, फिर पुलिस भेजकर रजिस्ट्रेशन कैंप उखाड़ दिया, आज फर्जी जांच का आदेश दिया है कि जांच होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या होगी जांच? हमने चुनावी घोषणा की थी कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो इसे लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि इस कदम से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं।

आप नेता ने कहा कि आज उन्होंने कहा है कि अगर आप उन्हें वोट दोगे तो वे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना लागू नहीं करेंगे। वे बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा बंद कर देंगे, वे आपकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। बीजेपी सबकुछ रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को महिला सम्मान योजना के नाम पर पंजीकरण कराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

पुलिस कमिश्नर को यह आदेश कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर दिया गया। कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के प्रधान सचिव एलजी ने दिल्ली की प्रत्येक महिला (18 वर्ष से अधिक) को आम आदमी पार्टी द्वारा की गई घोषणा के संबंध में मुख्य सचिव, दिल्ली और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पत्र लिखा है। 1000 प्रति माह, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वापस निर्वाचित होने पर राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलजी की इच्छा है कि मुख्य सचिव गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच कराएं। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

मेलबर्न में भारतीय टीम की शानदार वापसी

मेलबर्न। मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की है और खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में नौ विकेट गंवाकर 358 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 116 रन पीछे है। नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन शतक जड़ा। वह फिलहाल 105 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने अब तक 176 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया है। मोहम्मद सिराज भी दो रन बनाकर नाबाद हैं।

भारत ने शनिवार को पांच विकेट पर 164 रन से आगे खेलना शुरू किया और 194 रन जोड़े। इस दौरान भारत ने चार और विकेट गंवाए। शनिवार को ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए। नीतीश ने नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे वॉशिंगटन सुंदर के साथ आठवें विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी निभाई। सुंदर और नीतीश दोनों ने 150-150 गेंद खेलीं।

टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम के आठवें और नौवें नंबर के बल्लेबाज ने 150+ गेंदें खेली हों। दोनों ने संयुक्त रूप से 285 गेंदें खेलीं यानी करीब 48 ओवर बल्लेबाजी की। सुंदर 162 गेंद में एक चौके की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले यशस्वी जायसवाल 82 रन, रोहित शर्मा तीन, केएल राहुल 24 रन, विराट कोहली 36 रन और ऋषभ पंत 28 रन और रवींद्र जडेजा 17 रन बनाकर आउट हुए थे। जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप खाता नहीं खोल सके। नीतीश ने 171 गेंद में बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर शतक लगाया। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक है। उन्होंने टेस्ट में पहली बार पचास से ज्यादा रन बनाए और उस पारी को शतक में बदल दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचस कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना

नईदिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुरेन जैन और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कुल 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिन अन्य अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें कंपनी के चेयरपर्सन मनोज गौड़, कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार सिंह, मुख्य वित्तीय अधिकारी आर के पोरवाल और पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एम के वी रामा राव शामिल हैं। सेबी ने अपने 89 पृष्ठ के आदेश में कहा कि उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने O2 कंपनी का किया अधिग्रहण

नईदिल्ली। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने रू. 12,468 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर O2 पावर का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह सौदा न केवल जेएसडब्ल्यू एनर्जी के विस्तार योजनाओं का हिस्सा है, बल्कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के प्रति उसकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को भी दर्शाता है। O2 पावर सोलर एंड विंड एनर्जी के क्षेत्र में कार्यरत एक अग्रणी कंपनी है, जो वर्तमान में लगभग 2.3 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का संचालन कर रही है। इस अधिग्रहण से जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 10 गीगावाट के पार पहुंच जाएगी। यह सौदा कंपनी के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में बड़ा योगदान देगा और इसे अपने 2040 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

बजट 2025 में मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत

नईदिल्ली। केंद्र सरकार आगामी बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स दरों में कटौती पर विचार कर रही है। हालांकि, टैक्स छूट की सटीक सीमा का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। इस पर अंतिम निर्णय 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किए जाने से पहले लिया जाएगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट 2025-26 में 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स में कटौती कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के इस कदम का मकसद धीमी विकास दर के बीच अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन को बढ़ावा देना है। देश के कई बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागरिकों पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए इनकम टैक्स के रेट्स में कटौती करने का भी आग्रह किया है।

चालू खाता घाटा दूसरी तिमाही में मामूली घटी

मुंबई। देश का चालू खाता घाटा (कैड) 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मामूली घटकर 11.2 अरब डॉलर रहा। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.2 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। देश के बाह्य भुगतान परिदृश्य को बताने वाला कैड 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान 11.3 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.3 प्रतिशत था। आरबीआई ने कहा, भारत का कैड 2024-25 की दूसरी तिमाही में मामूली रूप से कम होकर 11.2 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) रहा, जो 2023-24 की दूसरी तिमाही में 11.3 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) था। चालू खाता घाटा अप्रैल-सितंबर (2024-25 की पहली छमाही) के दौरान, 21.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.2 प्रतिशत रहा।

2025 में वैश्विक नवाचार का पावर हाउस होगा भारत

रवि शर्मा

बीते दशक में भारत स्टार्टअप और नवाचार के लिए वैश्विक हब बनकर उभरा है। बढ़ते पूंजी प्रवाह, वैश्विक पहुंच के विस्तार और तकनीकी उन्नति के साथ देश 2025 में भी परिवर्तनकारी विकास के लिए तैयार है। हालांकि, इस गति को बरकरार रखने के लिए व्यवस्थागत चुनौतियों, जैसे- सीमित शिक्षा-उद्योग सहयोग और कमजोर संस्कृति का समाधान किया जाना जरूरी है।

पिछले दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय विकास हुआ है। वर्ष 2014 में पांच सौ से कम स्टार्टअप को मंजूरी मिली थी। वहीं 2023 तक यह संख्या बढ़कर 90 हजार तक पहुंच गई, जिनमें सौ से ज्यादा यूनिकॉर्न शामिल हैं। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। स्टार्टअप का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। शुरुआती क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और फिनटेक (जैसे फ्लिपकार्ट व पेटीएम) पर फोकस था। हाल ही में एआई, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स का लाभ उठाने वाले डीप-टेक स्टार्टअप के साथ-साथ हेल्थटेक, एग्रीटेक, एडटेक और क्लाइमेट टेक ने भी गति पकड़ ली है।

भारतीय स्टार्टअप अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों को लक्षित कर आगे बढ़ रहे हैं। वार्षिक स्टार्टअप फंडिंग 2014 के दो अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 25 अरब डॉलर से अधिक हो गई। पिछले दशक में संचयी फंडिंग 150 अरब डॉलर को पार कर गई है। फिनटेक सालाना आठ अरब डॉलर आकर्षित करता है, इसके बाद ई-कॉमर्स, एडटेक और हेल्थटेक का नंबर है। जलवायु तकनीक तेजी से बढ़ रही है, फंडिंग 35 फीसदी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है।

क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई द्वारा संचालित आईटी निर्यात 200 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। हेल्थकेयर बाजार के 372 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें टेलीमेडिसिन और प्रिसिजन मेडिसिन अग्रणी हैं। सौर और पवन ऊर्जा में निवेश से 2030 तक भारत के 500 गीगावाट लक्ष्य की ओर विकास होगा। डिजिटल भुगतान अपनाने और ग्रामीण विस्तार के कारण बाजार का आकार 200 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देंगे। फ्रेशवर्क्स और ब्राउजरस्टैक जैसी सफलता की कहानियों के साथ भारतीय स्टार्टअप तेजी से वैश्विक अवसरों की खोज कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जैसी नीतियां नवाचार, वित्त पोषण व सरलीकृत अनुपालन के लिए रूपरेखा प्रदान करती हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग कमजोर है, जो नवाचार को दबा रहा है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.65 फीसदी अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका का 2.8 फीसदी है।

वहीं, अमेरिका में 25 फीसदी से अधिक स्टार्टअप अकादमिक अनुसंधान से उत्पन्न होते हैं, जबकि भारत में मजबूत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र का अभाव है। हमारे यहां उद्यम के विफल होने को कलंक के रूप में देखा जाता है, जबकि सिलिकॉन वैली में इसका जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा, प्रतिभाशाली नवप्रवर्तक बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। ऐसे में, शिक्षा-उद्योग सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है।

संयुक्त शोध प्रयोगशालाएं स्थापित हों, विश्वविद्यालय संचालित स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिले। शोध एवं विकास के लिए फंडिंग बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिले। कुल मिलाकर, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तकनीकी प्रगति, वैश्विक विस्तार व सरकारी समर्थन से प्रेरित होकर 2025 तक पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है। नवाचार संस्कृति, अकादमिक-उद्योग साझेदारी को और वैश्विक बाजार पहुंच का विस्तार करके भारत 2025 में वैश्विक नवाचार पावरहाउस में बदल सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्तित्व निर्माण के साथ सेवा कार्यों पर विशेष आग्रह

अपने साथ सबको सुखी, सुरक्षित बनाना ही मानव धर्म

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं. 28 दिसंबर को उन्होंने विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ चर्चा की. इस दौरान पूजनीय सरसंघचालक ने सेवा कार्यों पर कार्यकर्ताओं व अधिकारियों का मार्गदर्शन किया.छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विचार परिवार द्वारा समाज के सहयोग से अनेक सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं.

सर्व धर्म समा वृत्तिः सर्व जाति समा मतिः. सर्व सेवा परानीति रीतिः संघस्य पद्धति.

अर्थात सभी धर्मों के साथ समान वृत्ति सभी जातियों के साथ समानता की मति बुद्धि, सभी लोगों के साथ परायणता का व्यवहार संघ की पद्धति है. सेवा को मानवता का धर्म भी कहा जाता है.

हमारे धर्म गंर्थों में सेवा के अनुकरणीय उदाहरण प्राप्त होते हैं. सेवा धर्म है, मेरे जीवन से सभी का जीवन सुखी हो, निरामय हो, मनुष्य की यही कल्पना होना चाहिये. यह हमारी प्राचीन परंपरा का आख्यान है. अपने साथ सबको सुखी, सुरक्षित बनाना ही मानव धर्म है. यदि केवल अपने हित की चिंता की तो वह धर्म नहीं है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के मूल में भी सेवा का भाव प्रमुख है. आद्य सरसंघचालक पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी के मन में देश की दुर्दशा को देख पीड़ा थी, यही कारण रहा कि संघ अपने जन्म के साथ ही सेवा रूप लेकर आया है. 1925 में संघ की स्थापना हुई थी. मार्च 1926 में राम नवमी के अवसर पर निकलने वाली यात्रा में स्वयंसेवकों ने सेवा की थी. यह आत्मीयता की भावना ही थी, हमारा सबके साथ आत्मीयता का रिश्ता है. स्वयंसेवक अपने आस पास के लोगों के दुख, दारिद्रय, अभाव को दूर करने के लिये प्रयास करें.

छत्तीसगढ़ में चल रहे सेवा के अनेक प्रकल्पः छत्तीसगढ़ में सिर्फ सेवा भारती द्वारा ही 99 सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं. इनमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर में संचालित मातृछाया प्रमुख हैं. यहां ऐसे बच्चों को आश्रय दिया जाता है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या जिन्हें परित्यक्त कर दिया गया है. इन बच्चों के भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा व मनोरंजन की उत्कृष्ट व्यवस्था मातृछाया में समाज के सहयोग से प्रदान की जाती है. इसके साथ ही 7 अलग-अलग स्थानों पर कन्या छात्रावास तथा 2 स्थान पर आश्रय गृह संचालित किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ प्रांत में 59 संस्कार केंद्र भी संचालित हो रहे हैं. इन संस्कार केंद्रों में बच्चों को स्वच्छता, श्रेष्ठ आचरण, राष्ट्र भक्ति, भोजन मंत्र के साथ सामूहिकता आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है. सेवा भारती द्वारा प्रांत में 11 किशोरी विकास केंद्र भी संचालित हो रहे हैं. इसी तरह अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सिलाई केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य पैथलैब एवं पॉलीक्लिनिक का संचालन भी अलग-अलग स्थान पर हो रहा है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शाखा के माध्यम से भी समाज के सहयोग से सेवा कार्य संचालित करता हैं. सेवा शिक्षण कार्य को पांच उपक्रमों में विभाजित किया गया है...

1.सेवा संस्कार-1

इनमें साप्ताहिक सेवा दिवस पर सुभाषित, अमृतवचन, गीत का अभ्यास शाखाओं में कराया जाता है.

2. सेवा संस्कार-2

इसी तरह सेवा कार्य व प्रकल्प की जानकारी, सेवा कथा, महापुरुषों के जीवन का स्मरण, अनुभव कथन, व शाखा में बौद्धिक चर्चा होती है.

3. सेवा बस्ती संपर्क

शाखा के माध्यम से सेवा बस्ती संपर्क कार्यक्रम भी संचालित होता है.

4. सेवा कार्य चलाने वाली शाखा

शाखा द्वारा दैनिक व साप्ताहिक स्थाई सेवा कार्य संचालित किए जाते हैं. रायपुर विभाग में ही ऐसे उपक्रम चलाने वाली शाखाओं की संख्या 61 है.

5. सेवा उपक्रमशील शाखा

ऐसी शाखाओं को शामिल किया जाता है, जो साल में न्यूनतम दो सेवा उपक्रम अवश्य करती हों. रायपुर में ऐसी शाखाओं की संख्या 54 है, जबकि रायगढ़ में 82 व दुर्ग में 77 है. (आरोग्य शिविर, शिक्षा उपयोगी साहित्य वितरण, बस्ती में सहभोज, महापुरुष पुण्यस्मरण, भजन आदि)

प्रेरणास्त्रोत कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित

रायपुर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, रायपुर के स्मृति मंदिर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी प्रेरणास्त्रोत है। विशेष रूप से भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जमवाल,संगठन महामंत्री श्री पवन साय सहित नेतागण मौजूद रहे।

नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां जोरों पर, लेकिन, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

रायपुर। नए साल 2025 के जश्न की तैयारी रायपुर में ज़ोरों पर है। इस बार 80 से अधिक होटलों, रेस्टोरेंट्स और फार्म हाउसों ने शराब परोसने के लिए अनुमति मांगी है, जिसे प्रशासन ने सख्त नियमों के साथ मंजूरी दी है। जश्न मनाने वालों को नियमों का पालन करना होगा, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

रात 12ः30 बजे तक बंद करने के निर्देशः आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यक्रम 31 दिसंबर की रात 12ः30 बजे तक बंद कर दिए जाएं। देर रात पार्टी करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजामः 500 पुलिस जवानों की तैनाती- शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

20 चेक पॉइंट्स पर निगरानी- शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार और अन्य कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी से होगी निगरानीः सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तेलीबांधा, वीआईपी रोड और नवा रायपुर जैसे इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी।

आबकारी विभाग की कड़ी नजरः आबकारी विभाग ने विशेष टीमें बनाई हैं, जो सुनिश्चित करेंगी कि होटलों और बार में शराब परोसने के समय का पालन हो। रात 12 बजे के बाद खुला पाया जाने पर जुर्माना और कार्रवाई होगी।

नाइट पेट्रोलिंग और सख्तीः 31 दिसंबर की रात विशेष नाइट पेट्रोलिंग टीम सक्रिय रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, स्टंटबाजी, कार रेसिंग या खुले में पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी गाइडलाइन के तहत आतिशबाजीः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। आतिशबाजी केवल तय स्थान और समय पर करने की अनुमति दी गई है।

आयोजकों के लिए खास गाइडलाइनः होटलों और रेस्टोरेंट्स को पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।

सड़क पर पार्किंग पाए जाने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्यक्रम नियमों और शांति व्यवस्था के तहत आयोजित हों।

नए साल का जश्न मनाने के दौरान सुरक्षा, समय और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उल्लंघन करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा शुरू

राजधानी पहुंची 30 टीमें, नेपाल से भी आए खिलाड़ी

रायपुर। साइंस कॉलेज ग्राउंड में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता का आगाज शनिवार को हुआ. राष्ट्रीय शोक की वजह से यह कार्यक्रम औपचारिक उद्घाटन के बाद शुरू हुआ. देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया. पूरे देश के लगभग 30 राज्यों के तीरंदाजी और फुटबॉल के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं. पड़ोसी देश नेपाल के खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं. कोटा स्टेडियम में फुटबॉल का मैच आयोजित होगा और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ग्राउंड में तीरंदाजी का गेम होगा.

24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता- आर्चरी गेम में माहिर खिलाड़ियों ने बताया कि वो तीरंदाजी के इस गेम को पिछले 2 साल से खेल रहे हैं. अब तक यह दूसरा नेशनल गेम रायपुर में खेल रहे हैं. साल 2023 में पहले नेशनल गेम उत्तर प्रदेश में खेला गया था. खिलाड़ियों ने बताया कि अंडमान निकोबार में टेंपरेचर नॉरमल होता है लेकिन दूसरे राज्यों में ठंड की वजह से तीरंदाजी में निशाना साधते समय कुछ दिक्कतें होती है. ठंड ज्यादा होने की वजह से तीरंदाजी के गेम में निशाना साध पाना मुश्किल होता है और परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाता है.

तीरंदाजी और फुटबाल का खेल- फुटबॉल खिलाड़ियों ने बताया कि वह फुटबाल और कबड्डी दोनों खेलते हैं, लेकिन कबड्डी में कम मेहनत की जरूरत पड़ती है और फुटबॉल में ज्यादा मेहनत दौड़ भाग होती है. कबड्डी का मैदान छोटा होने के साथ ही इसमें खिलाड़ियों की संख्या 14 होती है. फुटबाल का ग्राउंड बड़ा होने के साथ ही इसमें 22 खिलाड़ी दोनों तरफ होते हैं. फुटबॉल खिलाड़ी ने बताया कि वह पहली बार फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन पिछले 5 सालों से कबड्डी के गेम में माहिर हैं. पांच बार कबड्डी के क्षेत्र में नेशनल भी खेल चुके हैं।

नवपदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण

रायपुर । नवपदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर बलराम प्रसाद वर्मा ने केन्द्रीय जेल रायपुर के पुरूष सेल एवं महिला सेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जेल परिसर एवं जेल बैरकों की साफ सफाई तथा कैदियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन आहार का निरीक्षण किया जो संतोषजनक पाया गया।

जज ने जेल में स्थापित लीगल एड क्लिनिक के क्रियान्वयन का भी निरीक्षण किया और वहाँ उपस्थित होने वाले लीगल एड डिफेन्स कौन्सिल एवं न्यायमित्र (पी.एल.वी.) को वहाँ रहने वाले कैदियों को हरसंभव विधिक सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया एवं कोई भी बंदी बिना विधिक प्रतिनिधि / अधिवक्ता के न रहे यह सुनिश्चित करने को कहा गया।केन्द्रीय जेल रायपुर में बी.पी. वर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर भी किया गया जिसमें वहाँ उपस्थित कैदियों को लीगल एड क्लीनिक के कार्यशैली के बारे में जानकारी दी गई और कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया तथा व्यक्तिगत रूप से कैदियों की परेशानियों को भी उनके द्वारा सुना गया । केन्द्रीय जेल रायपुर में स्थापित हॉस्पिटल का भी निरीक्षण द्वारा किया गया वहाँ उपस्थित चिकित्सकों से मिलकर वहाँ भर्ती मरिजों की जानकारी ली गई और चिकित्सकों को निर्देशित किया गया कि मरिजों को कैदी या अपराधी ना समझते हुए केवल मरीज है यह समझकर मनवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हर संभव उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जावे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

ईडी कार्रवाई से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया भाजपा की दुर्भावना

रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर धरमपुरा स्थित घर पर ईडी ने दबिश दी है. शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. जिसमें पूर्व मंत्री को प्रतिमाह 50 लाख रुपए मिलने का जिक्र किया गया है. ईडी के एक्शन से प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस-भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है. कांग्रेस ने फिर केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा किया है. वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे जांच एजेंसी का दायित्व बताया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का इस कार्रवाई पर बयान सामने आया है. संचार प्रमुख शुक्ला ने कहा कि वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है. जब-जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाती है। अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं. इसलिए ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं का निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि बहुत बार ईडी ने छापा मारा है, किसी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं आया है.

ईडी केंद्रीय जाँच के आधार पर जाँच करती है : गुप्ता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर बस्तर से लेकर रायपुर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शनिवार को मारे गए छापों के मद्देनजर कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है, वह इनपुट के आधार पर है। श्री गुप्ता ने कहा कि चूँकि लखमा मंत्री भी रहे हैं और कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी बस्तर क्षेत्र के सामने आए हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत हैं रहा है कि कहीं-न-कहीं कुछ-न-कुछ दाल में कुछ काला तो जरूर है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि कवासी लखमा भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं और इस दौरान प्रदेश में 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भी हुआ है। यह चर्चा का विषय है कि कवासी लखमा का पूरा परिवार राजनीतिक रहा है और लखमा परिवार लगातार कुछ-न-कुछ मामलों में जनता के बीच चर्चा का विषय रहता है, अखबारों में आता है। झीरम घाटी नक्सली हमले के समय भी जनता में चर्चा का विषय था कि लखमा अकेले कैसे बच निकले? उन्हें मोटर साइकिल कैसे मिल गई? यह हमारा आरोप नहीं है, जनता कहती है।

ननि और पंचायत चुनाव वोटर्स लिस्ट का कार्य तेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां का दौर चल रहा है. चुनाव के मद्देनजर निर्वाचक नामावली की चेकिंग हो रही है. इसके साथ ही वोटर्स लिस्ट के प्रकाशन को लेकर भी तैयारियां हो रही है. 15 जनवरी 2025 को वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन होगा. नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 में वोटर्स लिस्ट के संसोधन का कार्य किया जा रहा है. निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम- नगरपालिका और पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और मौका मिल रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का काम तेज कर दिया है. नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में वोटर्स लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को किया जाएगा.मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी जानिए- छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव और मतदाता सूची का पहला प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा. उसके बाद दावे, आपत्तियां को लेकर आवेदन की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है. इस दिन तक वोटर्स दावा और आपत्ति जमा कर सकते हैं. 9 जनवरी 2025 तक दावा और आपत्तियों का निपटारा होगा. इसके बाद नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा।

सभी विकासखंडों को 4 केंद्रों के उन्नयन का दिया गया लक्ष्य

बिलासपुर। मुख्यमंत्री साय के सुशासन में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, इसी क्रम में कलेक्टर ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। कलेक्टर ने सभी विकासखंड में सीएचसी, पीएससी में आवश्यक सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली और स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नयन के लिए प्रस्ताव बनाकर देने के निर्देश दिए। सभी विकासखंडों को आगामी तीन माह में 4 स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का लक्ष्य दिया गया। कलेक्टर ने कहा के स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।मंथन में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण ने क्रमवार सभी बीएमओ से सीएचसी केंद्रों में व्याप्त समस्याओं और सुविधाओं के विस्तार के संबंध में आवश्यक संसाधनों की जानकारी ली। सभी विकासखंडों के बीएमओ द्वारा केंद्रों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए जरूरी संसाधनों के बारे में बताया गया और समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया गया। तखतपुर में सीएम की 50 बिस्तरों के अस्पताल उन्नयन की घोषणा और इस संबंध में जिला स्तर पर किए गए कार्यों की कलेक्टर ने जानकारी ली। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आवश्यक संसाधनों के विषय में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जानकारी दी।

अमित और यज्ञदत्त पुनः निर्वाचित

बिलासपुर। प्रा. अमित बघेल (बिलासपुर) देश के अग्रणी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पुनः निर्वाचित और यगदत्त वर्मा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश मंत्री के रूप में सत्र 2024-25 हेतु पुनः निर्वाचित हुए हैं। यह घोषणा आज अभाविप छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय रायपुर से की गई। अभाविप के प्रदेश कार्यालय से आज निर्वाचन अधिकारी अरुण गुप्ता द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार उपरोक्त दोनों पदों का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा एवं दोनों पदाधिकारी दिनांक 3 से 5 जनवरी 2025 को आयोजित अभाविप छत्तीसगढ़ के 57 वाँ प्रांत अधिवेशन राजनांदगांव में ही संपन्न होने वाले 57वाँ प्रदेश अधिवेशन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पुनः निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष प्रा. अमित बघेल बिलासपुर के निवासी हैं। कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में बीई की शिक्षा पश्चात एम टेक॥. की उपाधि प्राप्त करने आपने भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य किया और वर्तमान में आप गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में कंप्यूटर विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप वर्ष 2008 से परिषद के सदस्य हैं। परिषद में बिलासपुर महानगर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विभाग सहप्रमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे दायित्वों का आपने निर्वहन किया।

वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति की बैठक संपन्न

तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया की होगी ऑनलाईन मॉनिटरिंग

रायपुर। राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस साल से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यह जानकारी आज छत्तीसगढ़ के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति की बैठक दी गई। नवा रायपुर स्थित मंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में तेन्दूपत्ता संग्रहण, बांस की बहुउद्देशीय उपयोगिता और वनवासियों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

राज्य में वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्राहकों से 5500 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से क्रय किया जा रहा है। निजी क्रेताओं को प्रतिभूति राशि जमा करने की अवधि में 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही निजी गोदामों में भंडारण हेतु जमा सुरक्षा निधि की 100 प्रतिशत वापसी की सहमति भी दी गई।

बैठक में प्रबंध संचालक, वन विकास निगम द्वारा सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, और बैंकुठपुर में पाई जाने वाली पांच प्रजातियों के बांस का प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। इनमें रोपा, चांई, झींगी, कटंग और पहाड़ी बांस शामिल हैं। इन बांसों का उपयोग कागज, फर्नीचर, सजावटी सामान, टेंट, सेंट्रिंग, और सब्जी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 500 करोड़ रूपए मूल्य का बांस राज्य के कृषकों की भूमि पर उपलब्ध है। सब्जी उत्पादक कृषकों द्वारा प्रति वर्ष लगभग दस करोड़ रूपए के बांस का उपयोग किया जा रहा है।

बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण और रेलवे द्वारा बांस का उपयोग क्रेश बैरियर और फेसिंग में किया जा रहा है, जिससे यह काष्ठ, एल्युमिनियम और लौह का महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है।मंत्री केदार कश्यप ने बांस बाजार का विस्तृत सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल में निवासरत परिवारों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए समर्थन मूल्य पर अधिक लघु वनोपज के संग्रहण को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. निवास राव, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल साहू, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक बी. आनंद बाबू, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मती संजीता गुप्ता और उप सचिव मयंक पाण्डेय उपस्थित रहे।

डिप्टी सीएम साव ने वनांचल में लगाई चौपाल

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज लोरमी के वनांचल के गांवों में जन चौपाल लगाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। श्री साव ने अचानकमार में ग्रामीणों की मांग पर दुर्गा मंच और यात्री प्रतीक्षालय की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सर्दी में ठंड से बचाव के लिए ग्रामीणों को शॉल भी वितरित किए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव द्वारा अचानकमार के पूर्व माध्यमिक शाला में लगाई गई चौपाल में अचानकमार के साथ ही आश्रित गांवों सारसडोर, दावनखोर और सिवनखार के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने छपरवा और बिंदावल में भी चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं एवं मांगों की जानकारी ली। श्री साव ने ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं और आपके पास सुख-दुःख बांटने आया हूं। आप लोगों की समस्या मेरी समस्या है, और उन्हें हल करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि विगत 25 नवम्बर को जकरबांधा में मैंने अपने हजारों परिवारजनों के बीच अपना जन्मदिन मनाया था। इस दौरान लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों कहा कि विष्णु देव साय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की सभी प्रमुख गारंटी पूरी की है। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं-बहनों को 10 किस्त में 10 हजार रुपए दे दिए हैं। इस राशि का उपयोग परिवार के कल्याण के लिए करना है। उन्होंने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए राशि का सदुपयोग करने को कहा, ताकि वे पढ़ लिखकर तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीद रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.